● वर्ष-6
● अंक-98
रायपुर, शुक्रवार
20 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

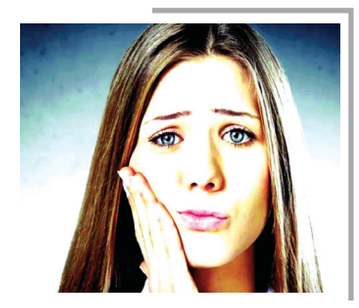

पेज-6>> मुंह की बदबू से लेकर मसूड़ों...

वेतन बढ़ाइये सिर्फ मुनाफा मत कमाइये, कंपनियों को दोटूक संदेश देते हुए कर्मचारियों के हक में खुद मोदी ने बुलंद की आवाज

नई दिल्ली। महंगाई से जूझती जनता की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ने खुद कंपनियों से पूछा है कि सैलरी कब बढ़ाओगे। यही नहीं, बायोडाटा लेकर घूमते युवाओं की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कंपनियों से पूछा है कि नौकरियां कब बढ़ाओगे? हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा, भैया, सरकार ने आपको टैक्स में इतनी बड़ी राहत दी, कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचाने के लिए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया, ल्स्ज्ञ में सुधार किए, कारोबार करना आसान बनाया, लेकिन आपने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया? क्या उनकी सैलरी बढ़ाई? क्या आपने अपनी कंपनियों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए? आखिर सरकार की ओर से दी जा रही राहत का फायदा आपके यहां काम करने वाले कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के सामने यही सवाल रखकर एक ऐसी बहस छेड़ दी है, जिसका सीधा संबंध देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों से है।

हम आपको बता दें कि दिल्ली में फिक्की के 100वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का यह अंदाज उद्योगपतियों के लिए किसी स्पष्ट संदेश से कम नहीं था। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया। सरकार ने कारोबारियों को निवेश और विस्तार के लिए बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले किए। इतना ही नहीं, 12 लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त करने का फैसला भी लिया गया, ताकि आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और बाजार में मांग का विस्तार हो।



लेकिन प्रधानमंत्री का सवाल था कि जब सरकार ने अपनी तरफ से इतनी बड़ी राहत दी, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई? क्या युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा की गईं? उनका जवाब भी उन्होंने खुद दिया- नहीं! कंपनियों का रवैया यही है कि मोदी जी, आप अपना काम कीजिए, हम बाद में देखेंगे।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर महीने अपनी मेहनत, समय और प्रतिभा से कंपनियों की तरक्की में योगदान देते हैं। किसी भी कंपनी की सफलता केवल उसके मालिकों, निवेशकों या प्रबंधन की उपलब्धि नहीं होती। उसके पीछे उन कर्मचारियों का भी पसीना होता है, जो अपने निर्धारित समय से आगे बढ़कर काम करते हैं, लक्ष्य पूरा करने के लिए दबाव झेलते हैं और कंपनी के कारोबार को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जब सरकार की नीतियों से उद्योग जगत को राहत मिलती है, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देना चाहिए। मोदी ने उद्योगपतियों को यह भी याद दिलाया कि टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहले जहां रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे, अब यह प्रक्रिया काफी तेज हुई है। ल्स्ज्ञ सुधारों के कारण अनेक उत्पादों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। इससे बाजार में मांग बढ़ने और उद्योगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना मजबूत हुई है। लेकिन इस आर्थिक गतिविधि का लाभ केवल कंपनियों के खातों और मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देखा जाये तो प्रधानमंत्री का संदेश केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने उद्योग जगत से उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, आयात पर निर्भरता घटाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का आह्वान भी किया। उनका कहना था कि 140 करोड़ लोगों का विशाल घरेलू बाजार उद्योगों के लिए सुविधा जरूर है, लेकिन इसे गुणवत्ता से समझौता करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

पुरानी सरकारों का अनुभव खट्टा था, अब देश में है दोस्त सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की 100वीं वार्षिक महासभा और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश-विदेश से आए उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की आर्थिक प्रगति, गरीबी उन्मूलन और भारतीय उद्योग जगत की भूमिका पर बात की। इतना ही नहीं, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आपका पुरानी सरकारों का अनुभव इतना खट्टा है कि उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। यह पुरानी सरकार नहीं है, यह दोस्त सरकार है। यह दोस्ती निभाना जानती है और आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। इसलिए बिना संकोच, बिना झिझक, मुझे खुलकर लिखकर भेजिए कि अभी भी क्या सुधार जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 100 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने कई दौर देखे हैं। देश ने लाइसेंस-कोटा राज देखा, राष्ट्रीयकरण का असफल प्रयोग भी देखा। इसके बाद 21वीं सदी में एक ऐसा दौर आया, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल फाइव में गिना जाने



महाशक्तियों की बैठकः ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन ने किया मंथन, यूक्रेन जंग से परमाणु निरस्त्रीकरण पर हुई चर्चा

शेनजेन। चीन के शेन्जेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक हुई। 33वें एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस बैठक में वैश्विक शांति, सुरक्षा, परमाणु निरस्त्रीकरण, ईरान से जुड़े संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तीनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रमुख शक्तियों की साझा जिम्मेदारी और आपसी संवाद की जरूरत पर जोर दिया। बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ पहले भी लंबी बातचीत की है और उन्हें लगता है कि युद्ध समाप्त करने की दिशा में कुछ प्रगति हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष युद्ध खत्म करना चाहते हैं और इस दिशा में प्रयास आगे बढ़ सकते हैं। बैठक की मेजबानी कर रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस त्रिपक्षीय मुलाकात को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग का उदाहरण पेश करना चाहिए। तीनों देशों को विश्व शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ मानव प्रगति में योगदान देना चाहिए।

दवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली। दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण से जुड़े नियम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं।

लेकिन क्या हर तरह के औषधीय उत्पादों पर एक जैसे नियम लागू होना सही है? इन्हीं सवालों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की तीन श्रेणियों के लिए नियमों में कुछ राहत देने का प्रस्ताव रखा है। इनमें मेडिकल गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थ शामिल हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब दिसंबर 2023 में दवाओं के निर्माण से जुड़े गुणवत्ता मानकों में बदलाव किए गए थे।



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और महानायकों को देशभर में नई पहचान दिलाई है। जनजातीय समाज के महानायकों ने देश की स्वतंत्रता, अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अतुलनीय संघर्ष और बलिदान दिया है। उनका योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आज जनजातीय गौरव दिवस केवल आदिवासी समाज का उत्सव नहीं, बल्कि

चक्रवात 'अकवान' हुआ भयंकर, 10 राज्यों में अलर्ट, छत्तीसगढ़ में भी बदलेगा मौसम

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अकवान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। 20 नवंबर को इसके आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों के बीच पहुंचने की आशंका है। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में तूफान का असर देखने



को मिल सकता है। ओडिशा के छह जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी है। वहीं, उत्तर प्रदेश में 21 और 22 नवंबर को बारिश के आसार हैं। 23 नवंबर से तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ सकती है। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 19 से 21 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी है। आईएमडी निदेशक के नागरात्ना ने बताया कि गंभीर चक्रवाती तूफान %अकवन% पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में है। यह आसपास के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। पिछले छह घंटों में यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। इसकी वर्तमान स्थिति 14.9 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। यह नारसापुर से लगभग 410 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अखिलेश के रोड शो में बच्चे की मौत

गोरखपुर। समाजवादी पार्टी के रोड शो के दौरान एक नाबालिग बच्चे की मौत के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। एक जन चौपाल को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने इस घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया।



उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उस मासूम का क्या कसूर था, जिसकी जान सपा की अराजकता की भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे आज खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाएंगे और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। सपा पर तीखा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में माफियाराज हावी था और समाजवादी पार्टी हमेशा से माफिया व अपराधियों की पर्याय रही है। इस दुखद घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अराजकता फैलाने वाले और माफियाओं को संरक्षण देने वाले इन लोगों के पास पीड़ित परिवार के लिए संवेदना के दो शब्द तक नहीं हैं।

आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला कथित दोहरे पैन कार्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। ईडी ने आजम खां को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के बाद ईडी की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। जिसमें ईडी की ओर से जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। साथ ही उनकी अर्तरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अदालतें सांविधानिक गरिमा की रक्षा के लिए असाधारण मामलों में दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन ऐसी राहत राजनीतिक गणनाओं के आधार पर न तो मांगी जा सकती है।



500 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ को तैयार

नई दिल्ली। दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आखिरी सक्रिय आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए कई मोर्चों से एक साथ आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने की रणनीति तैयार की जा रही है। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, लतीफ भट के मारे जाने से लश्कर को बड़ा झटका लगा है। अब पाकिस्तानी आतंकी संगठन सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तान में 500 से ज्यादा आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। ये आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बने लॉन्चपैड पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण उनकी घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं।

अमित बघेल को राहत हेट स्पीच के 14 मामलों में नियमित जमानत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 14 हेट स्पीच प्रकरणों में नियमित जमानत दी गई है। न्यायालय ने रायपुर जिले से बाहर निवास करने की शर्त भी हटा दी है। अमित बघेल जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये प्रकरण रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ से संबंधित वक्तव्य से जुड़े हैं। प्रकरण की सुनवाई के दौरान बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय को बताया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों में सात माह से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण भी किया है। राज्य शासन ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि बघेल के विरुद्ध इन 14 प्रकरणों के अतिरिक्त 19 अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त हैं। राज्य शासन ने यह भी कहा कि अस्थायी जमानत समाप्त होने पर बघेल ने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया।

एक ही परिवार के 5 लोगों के शव कुएं में मिले

करूर। तमिलनाडु के करूर जिले के पास चिन्नकालीपालयम गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव बगीचे के कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में दंपती, उनकी बेटी और दो मासूम बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में पारिवारिक विवाद को घटना की संभावित वजह बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, करूर जिले के वेंगामेडु स्थित कोंगुनगर निवासी रामासामी (63), उनकी पत्नी जानकी (60), बेटी सुकुना (35) और उनके दो बच्चे शिवानी (10) व अधिरन (4) के शव कुएं में मिले हैं। पांचों एक ही परिवार के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि रामासामी की बेटी सुकुना की शादी करीब 13 साल पहले वेलायुधमपालयम निवासी प्रभु से हुई थी। दंपती के दो बच्चे शिवानी और अधिरन थे। पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते सुकुना अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इस बीच, चिन्नकालीपालयम गांव में गुरुवार शाम स्थानीय लोगों ने बगीचे के कुएं में पांच लोगों के शव देखे। एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया।

म्यांमार में रोहिंग्या का कत्लेआमः दस हजार मौतों के सबूत मिले

नई दिल्ली। म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अहम सुनवाई चल रही है। गुरुवार को अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे सबूत हैं, जिनसे पता चलता है कि 2017 में म्यांमार की सेना ने करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या की थी। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

अदालत के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों को मारा। महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की गई। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। सेना ने उन लोगों पर भी हमले किए, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यह मामला करीब एक दशक पहले म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई से जुड़ा है।

रोहिंग्या म्यांमार का एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे। अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने इस इलाके में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। सेना ने दावा किया कि एक रोहिंग्या विद्रोही संगठन के हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोप लगे। सुरक्षा बलों पर रोहिंग्या नागरिकों की



हत्या करने, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और हजारों घरों को जलाने के आरोप लगे। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को अपना घर और गांव छोड़कर भागना पड़ा। जान बचाने के लिए लाखों रोहिंग्या सीमा पार करके पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंच गए। इस तरह म्यांमार में शुरू हुई सैन्य कार्रवाई एक बड़े शरणार्थी संकट में बदल गई।

म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में मामला कैसे पहुंचा?- म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा अफ्रीकी देश गाम्बिया ने दायर किया था। गाम्बिया ने 2019 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।

उसका आरोप है कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करके 1948 के नरसंहार रोकने संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है। इस समझौते के तहत किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समुदाय को पूरी तरह या उसके किसी हिस्से को खत्म करने की मंशा से किए गए अपराध नरसंहार के दायरे में आते हैं।

गाम्बिया चाहता है कि अदालत म्यांमार को ऐसी गतिविधियां रोकने का आदेश दे। साथ ही नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए। दूसरी तरफ, म्यांमार ने इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी। यह नरसंहार नहीं था। इस मामले में अदालत को यह तय करना है कि रोहिंग्या समुदाय को खत्म करने की मंशा से कार्रवाई की गई थी या नहीं।

म्यांमार छोड़ने के बाद करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर कॉक्स बाजार जिले के शिविरों में रहते हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग बेहद कम जगह में रहने को मजबूर हैं। उनकी जिंदगी आसान नहीं है। शिविरों में कई तरह की परेशानियां हैं।

बीमारियों का खतरा- शिविरों में साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है।

आग लगने का डर- भीड़भाड़ वाले शिविरों में आग लगने की आशंका रहती है। ऐसी घटनाएं बड़ी संख्या में लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं।

मानसून में मुश्किल- बारिश के मौसम में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इससे शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है।



नशे में कार से लोगों को कुचला, 4 गंभीर घायल, 9 वाहन क्षतिग्रस्त

जशपुर। नशे की हालत में तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने का खतरनाक परिणाम पालीडीह में देखने को मिला। जिंदल बजाज मोटरसाइकिल शोरूम के सामने बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दो चारपहिया वाहन और सात मोटरसाइकिल समेत कुल नौ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावहता देखी जा सकती है। वहीं, पत्थलगांव पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना 16 नवंबर की शाम करीब 5 बजे की है। बटुराबहार निवासी बोधलाल नायक अपने भतीजे खेमचंद नायक और साथी सीताराम नायक व संदीप चौहान के साथ मोटरसाइकिल खरीदने पालीडीह स्थित बजाज शोरूम पहुंचे थे। सभी ने अपनी कार और मोटरसाइकिल शोरूम के सामने सड़क किनारे खड़ी की थी और मोटरसाइकिल देखने के लिए अंदर चले गए। इसी दौरान उनका दोस्त विके बंजारा भी अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा था। शाम को जब सभी लोग शोरूम से बाहर निकले, तभी पाकरगांव की ओर से आ रही कार क्रमांक ष्टत्र13ह्न1090 का चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए गलत दिशा में पहुंच गया। कार ने सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट डिजायर और आल्टो कार सहित कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी कार की चपेट में आ गए। हादसे में खेमचंद नायक, सीताराम नायक, संदीप चौहान और विके बंजारा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार के शोरूम के सामने पहुंचने और वहां खड़े वाहनों को टक्कर मारने का घटनाक्रम देखा जा सकता है। हादसे के बाद आरोपी चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार सड़क के डिवाइडर के गड्ढे में फंस गई। इसके बाद वह कार से उतरकर भागने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान घनश्याम यादव (21 वर्ष), निवासी पालीडीह धनियापारा, थाना पत्थलगांव के रूप में हुई है। घटना के समय वह नशे की हालत में था। दुर्घटना में स्विफ्ट डिजायर कार और आल्टो कार के अलावा सात मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुईं। मामले में बोधलाल नायक की रिपोर्ट पर पत्थलगांव पुलिस ने अपराध क्रमांक 276/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 एवं 324(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। पूछताछ में आरोपी घनश्याम यादव ने घटना करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने दुर्घटना में प्रयुक्त आर्टिगा कार को जब्त कर लिया।

बलौदाबाजार में जिला युवा उत्सव, लोक संस्कृति और प्रतिभा का दिखा संगम

बलौदाबाजार। युवा प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से बलौदाबाजार में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2026-27 का आयोजन किया गया। योग भवन में आयोजित इस उत्सव में कई युवाओं ने लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, कविता लेखन और पारंपरिक वेशभूषा जैसी विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजन में 300 से अधिक युवाओं की भागीदारी रही। प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब राज्य



स्तरीय युवा उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित युवा उत्सव का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा गोलू जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, राज्य स्काउट के उपाध्यक्ष विजय केसरवानी, के के। वर्मा और योगेश वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककला और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। युवाओं ने लोकनृत्य और लोकगीत के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत किया, वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए सामाजिक विषयों को उठाया। चित्रकला, कविता लेखन और पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता दिखाई। इस आयोजन में केवल पारंपरिक विधाएं ही नहीं, बल्कि क्रिएटिव यूथ रील चैलेंज जैसी आधुनिक रचनात्मक विधा को भी शामिल किया गया। इससे युवा उत्सव में परंपरा और आधुनिक अभिव्यक्ति दोनों का मेल देखने को मिला। जिला खेल अधिकारी प्रीति बंछोर ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

नक्सली कमांडर हिडमा के बारूदी नक्सली ड़प से 670 बीजीएल शेल विस्फोटक बरामद

जगदलपुर। आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास पोलावरम के जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने एक संयुक्त अंतरराज्यीय अभियान चलाकर नक्सलियों द्वारा छुपाए गए विस्फोटकों और चिकित्सा सामग्री का बड़ा नक्सली ड़प बरामद किया है। इस डंप से 670 जिंदा बीजीएल शेल के अलावा डेटोनेटर, गन पाउडर, फ्यूज और दूसरी विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह विस्फोटक डंप नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा से जुड़ा हुआ है। हिडमा के मारे जाने के बाद से सुरक्षाबल लगातार उसके ठिकानों और छिपाए गए सामान की तलाश कर रहे थे। यह बरामदगी उन खुफिया सूचनाओं के बाद हुई है, जिनमें नक्सली नेता माड़वी हिडमा द्वारा विस्फोटक डंप छुपाए जाने की बात सामने आई थी। हिडमा पिछले साल मारेदुमिल्ली के पास जंगल क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया था।



पोलावरम जिले के पुलिस अधीक्षक के. चक्रवर्ती ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सीआरपीएफ कर्मियों के साथ चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान अंतरराज्यीय सीमा के पास एक नक्सली डंप से भारी मात्रा में विस्फोटक और आवश्यक चिकित्सा सामग्री बरामद की गई है। उन्होने बताया कि गठित एक विशेष टीम ने सीआरपीएफ की सहायता से लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के बाद सीमा क्षेत्र में इस अभियान को अंजाम दिया और जमीन में छुपाकर रखी गई सामग्री को बाहर निकाला। बरामद विस्फोटक डंप नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा से जुड़ा हुआ है।

पोलावरम जिले के पुलिस अधीक्षक के. चक्रवर्ती के अनुसार जब्त किए गए जखीरे में 670 जिंदा बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) शेल, 42 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 250 ग्राम बारूद, 12 बूस्टर या विस्फोटक रिंग, सात जिंदा भरमार कारतूस और लगभग छह मीटर फ्यूज शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने डंप से आवश्यक दवाओं और मेडिकल किट बॉक्स सहित 20 प्रकार की चिकित्सा सामग्री भी बरामद की है। इसमें जरूरी दवाइयां और मेडिकल किट बॉक्स शामिल हैं।पुलिस अधीक्षक के. चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि जिले और आस-पास के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों द्वारा छुपाए गए अन्य विस्फोटक डंपों की पहचान करने और उन्हें बरामद करने के लिए तलाशी तथा कॉम्बिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।

इस पूरे अभियान में सीआरपीएफ की 212 बटालियन, कोबरा 204 और 196 बटालियन के जवान शामिल थे। अभियान के दौरान 212 बटालियन के सेकेंड-इन-कमांड दिनेश कुमार और पोलावरम जिले के अधिकारियों सहित पुलिस व सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डिप्टी अरुण साव का कार्यक्रम में विधायक ईश्वर साहू ने लगाए ठुमके

बेमेतरा। नगर पंचायत मारो में डिप्टी सीएम अरुण साव का कार्यक्रम बुधवार को हुआ। ।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने की। विशिष्ट अतिथि की रूप में विधायक ईश्वर साहू मौजूद रहे। नगर पंचायत मारो में कार्यक्रम के दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू का अनोखा अंदाज देखने को मिला।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी कलाकारों का डांस भी रखा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद जनता ने विधायक ईश्वर साहू को भी डांस करने को कहा। इसके बाद विधायक ने भी लोगों की डिमांड पूरी करते हुए कलाकारों के साथ ठुमके लगाए। विधायक के ठुमकों का वीडियो चर्चा में भी है।

वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। नगर



पंचायत के वार्ड क्रमांक 03 में 75 लाख 20 हजार रुपये की लागत से बनने वाले डॉ। भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन का विधिवत भूमिपूजन किया गया। वहीं नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 2 करोड़ 31 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी गई है।

अरुण साव ने मारो नगर पंचायत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने हाट बाजार निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये और दुकान कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके साथ ही नगर में स्वच्छ पेयजल की समस्या के समाधान और बेहतर जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 30 करोड़ रुपये की जल आवर्धन योजना की भी घोषणा की।

कबीरधाम में 13 मामलों में 800 क्विंटल से अधिक धान जब्त

कवर्धा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही दूसरे राज्यों से अवैध धान लाकर खपाने का खेल तेज हो गया है। मध्यप्रदेश और अन्य सीमावर्ती राज्यों से सस्ते दामों पर धान खरीदकर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर बेचने की आशंका के बीच कबीरधाम जिला प्रशासन ने ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट बनाकर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध धान कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब तक जिले में अवैध धान परिवहन और कारोबार के 13



मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए 800 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है। इसके अलावा अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे करीब 10 वाहनों को भी जब्त किया गया है। इस पूरे अभियान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई 17 नवंबर को सामने आई। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश पासिंग वाहन क्रमांक यूपी 70एलटी 9660 से 755 बोरी धान बरामद किया गया।

इसका कुल वजन करीब 302 क्विंटल बताया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में धान मिलने के बाद दूसरे राज्य से धान लाकर स्थानीय खरीदी व्यवस्था में खपाने की आशंका जताई जा रही है।

अवैध धान के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य, मंडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें लगातार मैदान में सक्रिय हैं। सीमावर्ती रास्तों, मुख्य मार्गों और संदिग्ध परिवहन पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध कारोबार और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

बलौदाबाजार में बिरयानी सेंटर पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पंजीयन निलम्बित

बलौदाबाजार। लोगों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले में सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बलौदाबाजार और कसडोल क्षेत्र के होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम जब बिरयानी सेंटर पहुंची तो वहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं।

कुकिंग एरिया में अत्यधिक गंदगी थी, जबकि वाशिंग एरिया में पानी जमा मिला। तैयार खाद्य पदार्थों जैसे चिकन बिरयानी, रोस्ट और चिल्ली में कृत्रिम खाद्य रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम ने मौके पर ही ऐसे खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया। निरीक्षण में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली। स्टोर एरिया में खाद्य सामग्रियों का रखरखाव भी अव्यवस्थित पाया गया। कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में भी लापरवाही सामने आई। कर्मचारी हेड कवर, मास्क और एप्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वहीं पेस्ट कंट्रोल और मक्खियों से बचाव के लिए फ्लाई ट्रैप से जुड़े अनिवार्य दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं मिले। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन पांच दिनों के लिए निलंबित किया है। कमियां दूर होने और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित होने तक संचालन पर रोक लगाई गई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

धरने पर बैठी आगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला पर आई माता

धमतरी। धमतरी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की तीन दिवसीय हड़ताल का बुधवार को आखिरी दिन था। अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर 2300 से अधिक कार्यकर्ता-सहायिकाएं धरने पर बैठी थीं। इस दौरान धरना स्थल पर ऐसा अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंदोलन के बीच देवी बनाकर पूजा पाठ करना उस वक्त भारी पड़ गया, जब एक महिला को सच में माता आ गई। आनन-फानन में उसे धूप दिखाकर शांत कराया गया। दरअसल, प्रदर्शन के दौरान एक महिला कार्यकर्ता को काली माता के रूप में सजाया गया। उनके हाथ में खप्पर और उसमें जलती आग रखी गई। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताएं आरती उतारती नजर आईं। इस दौरान देवी सेवा गीत भी गाए जा रहे थे और धरना स्थल पर हंसी-मजाक का माहौल भी बना हुआ था।इसी बीच कंकालिन देवी के गीत के दौरान अचानक एक महिला कार्यकर्ता को सवारी आने की बात सामने आई। देखते ही देखते धरना स्थल का माहौल बदल गया।

छात्र-छात्राओं का शराब और सिगरेट पीते वीडियो वायरल

कोरबा। कोरबा जिले में स्कूली बच्चों के नशा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। मामले में एक्शन लेते हुए स्कूल के प्राचार्य ने 2 छात्राओं और 5 छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (ञ्जष्ट) का नोटिस थमा दिया है। पूरा मामला पाली ब्लॉक के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल धतूरा का है और यह वीडियो 14 नवंबर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 9वीं कक्षा की दो छात्राएं शराब और सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है। वहीं पांच छात्र स्कूल से बाहर जाकर गांजा पीते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। प्राचार्य बलभद्र सिंह ने स्कूल प्रबंधन समिति (स्ख्ष्ट) और विद्यार्थियों के परिजनों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद दो छात्राओं और पांच छात्रों समेत कुल 7 विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (ञ्जष्ट) देने का नोटिस जारी किया गया है। मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र के माध्यम से भेजी गई है।

बालोद में मुक्तिधाम से बुजुर्ग महिला की अस्थियां चोरी

बालोद। जिले में बुजुर्ग महिला की अस्थियां मुक्तिधाम से चोरी हो गईं। अंतिम संस्कार के दूसरे दिन परिजन चिता स्थल पर पहुंचे तो वहां नारियल, दिया और अगरबत्ती रखे मिले। राख में अस्थियां तलाशने पर वे गायब मिलीं। यह देखकर परिजन हैरान रह गए। उन्होंने थाने में शिकायत कर अस्थियां तलाशने की मांग की है। गांव में इस तरह की तीसरी घटना सामने आने से ग्रामीणों में आक्रोश और दहशत है। दरअसल, गुरुर ब्लॉक के ग्राम खैरवाही निवासी 94 वर्षीय विद्यावती रुखमणी शर्मा का 12 नवंबर की रात 11 बजे निधन हो गया था। 13 नवंबर को दोपहर साढे 12 बजे गांव के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके अगले दिन 14 नवंबर को शाम को उनके बड़े बेटे बालमुकुंद शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पूजा करने मुक्तिधाम पहुंचे। वहां चिता स्थल पर नारियल और दिया रखा देखकर वे हैरान रह गए। पहले उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब चिता की ठंडी हो चुकी राख में अस्थियां तलाशीं तो वे गायब मिलीं। इसके बाद ग्रामीणों को इसकी सूचना दी गई।

दीपा सागर मौत मामला में सुसाईड नोट की होगी जांच

जगदलपुर। जगदलपुर में दीपा सागर की मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। इस मामले में निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग कर रहे परिजनों ने अब पुलिस को दो महत्वपूर्ण चीजें सौंपी हैं। इनमें दीपा सागर का मोबाइल फोन और उनकी स्वाभाविक लिखावट वाली एक कॉपी शामिल है। पुलिस अब मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के जरिए डिजिटल साक्ष्य जुटाएगी। वहीं कथित सुसाइड नोट की लिखावट का दीपा की वास्तविक हैंडराइटिंग से मिलान कराया जाएगा। परिजनों ने शुरुआत से ही मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी बताया गया था। इसके बाद मोबाइल से जुड़ी जानकारियों और कॉल डिटेल को लेकर भी परिवार ने सवाल उठाए थे। अब जांच के लिहाज से मोबाइल फोन और हैंडराइटिंग के नमूने पुलिस को सौंपे गए हैं। मोबाइल को विधिवत जब्त कर एफएसएल रायपुर भेजने की तैयारी है, जबकि लिखावट के मिलान के लिए दीपा की कॉपी पीएचक्यू में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजी जाएगी।

कांकेर वेयरहाउस के गोदाम में कीड़े युक्त चावल मिलने का वीडियो

कांकेर। सरकारी चावल की गुणवत्ता को लेकर कांकेर में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के एक गोदाम से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सरकारी चावल और सप्लाई की गई बोरियों में कीड़े दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। ये गोदाम छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की कांकेर शाखा के करप में स्थित है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संबंधित चावल राइस मिलरों द्वारा सप्लाई किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, चावल की वास्तविक स्थिति, मात्रा और सप्लाई करने वाले मिलरों की जानकारी की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने और विभाग का पक्ष सामने लाने ईटीवी भारत की टीम समेत कुछ मीडियाकर्मी करप स्थित वेयरहाउस गोदाम पहुंचे। टीम ने अधिकारियों से चावल की गुणवत्ता और वीडियो को लेकर सवाल किए, लेकिन अधिकारियों ने जानकारी देने के बजाय वहां किसी के आने की परमिशन नहीं होने की बात कहते हुए परिसर से बाहर जाने के लिए कहा।

जशपुर में नालंदा परिसर, 11.29 करोड़ से बन रही 500 सीटर लाइब्रेरी

जशपुरनगर। बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में जशपुर में महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की स्वीकृति से जिला मुख्यालय में 11।29 करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। करीब एक एकड़ जमीन पर विकसित हो रहे इस आधुनिक परिसर में एक साथ 500 छात्र और युवा बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और अब तक लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। नगरपालिका ने अप्रैल 2027 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय के सामने बन रहे इस भवन में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया



जा रहा है। परिसर में पांच बड़े अध्ययन कक्ष बनाए जा रहे हैं, जहां एक साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। हर स्टडी रूम में टेबल-कुर्सी, पर्याप्त रोशनी और पंखे की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा परिसर में गार्डन भी विकसित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए शांत और अनुकूल वातावरण मिल सके। इस नालंदा परिसर को 24 घंटे संचालित करने की योजना है। यहां अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थियों को कैफेटेरिया यानी कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय ने बताया कि नालंदा परिसर को केवल सामान्य पुस्तकालय के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक अध्ययन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यहां विद्यार्थियों को प्रिंट पुस्तकों के साथ डिजिटल पुस्तकों के अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ई-पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी मोबाइल और लैपटॉप पर विभिन्न विषयों की पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री पढ़ सकेंगे। परिसर में हाईस्पीड वाई-फाई भी लगाया जाएगा, जिससे ऑनलाइन अध्ययन और इंटरनेट आधारित शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग आसानी से किया जा सकेगा। नालंदा परिसर में किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन की ओर से अलग से बजट उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तकालय के संचालन की जिम्मेदारी नगरपालिका संभालेगी। यहां विद्यार्थियों को अलग-अलग विषयों की पुस्तकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। ई-पुस्तकालय और इंटरनेट सुविधा के कारण विद्यार्थी केवल उपलब्ध पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल माध्यम से देश-दुनिया के साहित्य और विभिन्न शैक्षणिक विषयों की सामग्री तक भी पहुंच बना सकेंगे। वर्तमान में जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से एक पुस्तकालय संचालित किया जा रहा है, जहां विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा अध्ययन करते हैं। हालांकि, 500 सीटों की क्षमता वाले नालंदा परिसर के शुरू होने से विद्यार्थियों को एक बड़े और आधुनिक अध्ययन केंद्र का विकल्प मिलेगा। विशेष रूप से ऐसे युवाओं के लिए यह सुविधा उपयोगी होगी, जिन्हें घर पर पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, पर्याप्त जगह या इंटरनेट आधारित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

कच्चे सोने का लालच देकर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार। कच्चा सोना सस्ते में खरीदने का लालच एक ग्रामीण युवक को 20 हजार रुपये का चूना लगा गया। आरोपी ने सोने जैसा दिखने वाला टुकड़ा थमाया, युवक ने पैसे दे दिए, लेकिन अगले दिन धूप में टुकड़े की असलियत सामने आई तो वह नकली निकला। इधर, इसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के फड़ पर दबिश देकर 11 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके कब्जे से 44 हजार 200 रुपये नगद जब्त किए गए। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने एक ही दिन में ठगी और जुए के खिलाफ दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। दोनों मामलों की पूरी जानकारी थाना प्रभारी हेमंत पटेल



ने श्वञ्जङ्क भारत को दी।

ठगी का यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पुलिस के मुताबिक ग्राम सिनोधा निवासी 19 वर्षीय उमेश कुमार वर्मा को कच्चा सोना सस्ते में मिलने का झांसा दिया गया। 16 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे राहुल यदु नाम के व्यक्ति ने फोन कर उसे बताया कि ग्राम गोरदी का पोषण गिरी गोस्वामी कच्चा सोना बेच रहा है। इसके बाद पोषण ने खुद उमेश से संपर्क किया और उसे सोनबरसा के पास मिलने बुलाया। रात करीब 9 बजे तालाब के पास मुलाकात हुई। यहां आरोपी ने युवक को सोने जैसा दिखने वाला एक टुकड़ा दिखाया और उसके बदले 20 हजार रुपये नकद ले लिए। युवक को लगा कि उसे सस्ते में सोना मिल गया है। लेकिन असली खेल अगले दिन सुबह सामने आया।जब उमेश ने उस टुकड़े को धूप में अच्छी तरह देखा तो उसे पता चला कि जिसे वह सोना समझकर खरीद लाया था, वह नकली है। युवक ने जब आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने रकम लौटाने से इनकार कर दिया और धमकाकर वहां से चला गया। ठगी का अहसास होने पर उमेश ने 17 नवंबर को भाटापारा ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ममता साहू ने की भेंट



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को आगामी 23 नवंबर 2026 को मानव तस्करी एवं घरेलू हिंसा विषय पर आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

राज्यपाल से आईआईएमयूएन की चार्ज डी अफेयर्स अंबर फातिमा ने की सौजन्य भेंट



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से भारत के युवाओं में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यरत संस्था इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (आईआईएमयूएन) की चार्ज डी अफेयर्स सुश्री अंबर फातिमा ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को आगामी माह बिलासपुर में प्रस्तावित यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में बतौर मुख्य तिथि आमंत्रित किया।

राजधानी की स्वच्छता पर सियासत, मो. अकबर के बयान पर साव का पलटवार



रायपुर। राजधानी की स्वच्छता पर सियासत होने लगी है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के सफाई के लिए विधानसभा वार टेंडर पर पुनर्विचार और वार्ड स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहकर कुछ नहीं करती। हमारी सरकार शहर कैसे स्वच्छ और सुंदर बने, इस पर काम कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शहरों को इनाम मिल रहे हैं। यह बताता है कि हम स्वच्छता के क्षेत्र में किस तरीके से कम कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं की सुरक्षा पर कटौती पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि गृह विभाग सुरक्षा के मापदंड तय करता है। सारी बातों का समीक्षा करके ही इस बारे में निर्णय लिया गया है।

21, 24 और 26 दिसंबर को रद्द रहेगी टिटलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों



के परिचालन को लेकर रेलवे ने जरूरी अपडेट जारी किया है। पूर्व तटीय रेलवे के संबलपुर मंडल के बृंदामल स्टेशन में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दिसंबर में कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान टिटलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर को तीन दिनों 21, 24 और 26 दिसंबर 2026 को टिटलागढ़ और बिलासपुर दोनों ओर से नहीं चलेगी। वहीं, विशाखापत्तनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से देरी से रवाना होगी। रेलवे के मुताबिक, बृंदामल स्टेशन पर बृंदामल-झारसुगुड़ा फ्लाईओवर लाइन की कनेक्टिविटी के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 58213/58214 टिटलागढ़-बिलासपुर-टिटलागढ़ पैसेंजर को तीन दिनों के लिए रद्द किया गया है। यह ट्रेन 21, 24 और 26 दिसंबर 2026 को टिटलागढ़ और बिलासपुर दोनों ओर से नहीं चलेगी। इससे इन तारीखों में इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है। वहीं नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य का असर हीराकुंड एक्सप्रेस पर भी पड़ेगा। गाड़ी संख्या 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस 26 दिसंबर 2026 को विशाखापत्तनम से अपने निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से रवाना होगी।

भारत मंडपम में आज गूंजेगी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति

राज्य दिवस पर पारंपरिक नृत्यों की होगी भव्य प्रस्तुति, राज्यपाल डेका होंगे मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री साय करेंगे समारोह की अध्यक्षता

रायपुर। देश की राजधानी में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शुक्रवार, 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और पारंपरिक कलाओं का भव्य प्रदर्शन करेगा। भारत मंडपम नई दिल्ली के एम्फी थिएटर-01 में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह में प्रदेश के लोक कलाकार सात पारंपरिक नृत्य शैलियों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे। शाम पांच बजे से आयोजित होने वाले इस समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

इस सांस्कृतिक संध्या का विशेष आकर्षण छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकनृत्य होंगे। इनमें गौर नृत्य, गौरा-गौरी, भोजली, राउत नाचा, सुआ, पंथी और करमा नृत्य की प्रस्तुतियां शामिल हैं। इन लोकनृत्यों के माध्यम से प्रदेश के जनजातीय जीवन, सामाजिक परंपराओं, लोक आस्थाओं और ग्रामीण संस्कृति की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी। पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्ययंत्रों और संगीत की संगत में कलाकारों की प्रस्तुतियां दिल्ली के दर्शकों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दुनिया से रूबरू कराएंगी।

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की विशेषता उसकी विविधता और सामुदायिक जीवन से जुड़ाव है। गौर नृत्य बस्तर की जनजातीय परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। गौरा-गौरी और भोजली लोक आस्था एवं पारंपरिक उत्सवों से जुड़े हैं। राउत नाचा



छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा और यादव समाज की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। वहीं सुआ नृत्य महिलाओं की सामूहिक लोक अभिव्यक्ति, पंथी नृत्य सतनाम पंथ की आध्यात्मिक परंपरा और करमा नृत्य जनजातीय जीवन, प्रकृति तथा सामूहिक उल्लास का प्रतीक है।

राज्य दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, निगम- मंडल एवं आयोगों के अध्यक्षों सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रहेगी। संस्कृति एवं राजभाषा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और देश-विदेश से आने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है।

उल्लेखनीय है कि भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ का पवेलियन भी देश-विदेश के आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पवेलियन में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय हुनर और विकास की संभावनाओं को एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां बस्तर की प्रसिद्ध बेलमेटल कला, जनजातीय आभूषण, पारंपरिक हस्तशिल्प, चांपा की कोसा सिल्क, हथकरघा वस्त्र और वनोपज से तैयार हर्बल उत्पाद विशेष आकर्षण हैं। कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट उत्पाद प्रदेश की कृषि एवं वन संपदा की पहचान प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्रकोट जलप्रपात का 3D वर्चुअल रियलिटी अनुभव आगंतुकों को बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ रहा है। वहीं स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप के नवाचार, नए उत्पाद और व्यावसायिक पहल छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार एवं उद्यमिता की बढ़ती संभावनाओं को दर्शा रहे हैं।

भाजपा ने ओबीसी को सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी देकर सम्मान दिया है: अमरपाल

कांग्रेस की राजनीति एक परिवार तक सीमित थी

रायपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आहूत संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने कहा कि ओबीसी मोर्चा ने पूरे छत्तीसगढ़ में मण्डल स्तर तक संगठन की संरचना को पूर्ण कर लिया है। अब हमारा संकल्प है कि संगठन की शक्ति को जिला, मण्डल और बूथ तक लेकर जाएँ ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उनमें भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की सबसे अग्रणी भूमिका रहे। श्री मौर्य ने कहा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा का काम केवल संगठन बनाना नहीं है, बल्कि सभी समाज के साथ समन्वय और संवाद स्थापित करना है।

मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनको समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना ही हमारा मूल संकल्प है। श्री मौर्य ने कहा कि देश की आजादी के बाद से ओबीसी समाज के प्रति कांग्रेस सरकारों की बड़ी उदासीनता रही है। कांग्रेस ने ओबीसी की हमेशा चर्चा की, लेकिन ओबीसी के जीवन के उत्थान में उनकी भूमिका क्या रही, यह सब जानते हैं। कांग्रेस की राजनीति एक परिवार तक सीमित थी। श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी ने 70 साल की व्यवस्था को बदला है। जिनको समाज की राजनीतिक सत्ता से दूर रखा गया था, उनको देश में अग्रणी भूमिका में लाने का काम भाजपा और मोदी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार निरन्तर इसी दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इस लक्ष्य में ओबीसी समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। जो समाज मुख्यधारा से छूट गया है, उसे मुख्यधारा में लाना, उसे शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान और राजनीतिक हिस्सेदारी देना, यही हमारा चिंतन है। इसी को लेकर हम समाज के बीच में जाने वाले हैं। श्री मौर्य ने कहा कि भाजपा ने ओबीसी को सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी देकर सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो देश के इतिहास में पहली बार केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री बने। छत्तीसगढ़ सरकार में भी 14 में से 7 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भाजपा का संकल्प है कि जो समाज छूटा था, उसे आगे लेकर आएँ।

मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस के लोग संसद में और प्रदेशों की सत्ता में रहे, लेकिन जब उनको ओबीसी समाज की गिनती का काम करना था, तब उन्होंने नहीं किया। आज जब जनगणना हो रही है, तो उसमें भी उनको परेशानी है और कमियाँ निकालने का काम कर रहे हैं। श्री मौर्य ने कहा कि जीवन में कुछ करने का भी संकल्प होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा काम व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। कांग्रेस को अब केवल आलोचना की राजनीति से बाहर आकर समाज के हित में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। श्री मौर्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ का पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करेगा, समाज के हर वर्ग से संवाद करेगा और भाजपा की विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाएगा। इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी छगन साहू एवं सह प्रभारी श्रवण यदु मौजूद रहे।

भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, त्याग और बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा : वित्त मंत्री

भगवान बिरसा मुंडा चौक पर प्रतिमा का माल्यार्पण कर किया नमन

रायपुर। वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज जशपुर प्रवास के दौरान भगवान बिरसा मुंडा चौक पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य साहस, त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान में उनके ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान जननायक, समाज सुधारक और जनजातीय अस्मिता एवं स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उन्होंने अल्पायु में ही अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। जनजातीय समाज को संगठित कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और जल, जंगल तथा जमीन की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका संपूर्ण जीवन साहस, संघर्ष, सामाजिक चेतना और राष्ट्रप्रेम की अनुपम मिसाल है। चौधरी ने कहा कि भगवान



बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज में आत्मसम्मान, एकता और अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा समाज को संगठित और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका संघर्ष केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अस्मिता और जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए भी था। उनके विचार और आदर्श आज भी समाज को एकता, स्वाभिमान और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देते हैं।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष और बलिदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जूदेव, कृष्णा राय, भरत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अमित बघेल को हेट स्पीच के मामले में मिली नियमित जमानत

रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक एवं जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को हेट स्पीच से संबंधित 14 आपराधिक प्रकरणों में नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है।

बता दें कि अमित बघेल के खिलाफ मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं। रिपोर्टों के मुताबिक, इस विवाद में कुल 14 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी।

गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का



निर्देश दिया गया था. उक्त सशर्त अंतरिम जमानत की अवधि 22.10.2026 को समाप्त हो गई थी। अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने बुधवार को अदालत में सरेंडर किया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने 28.10.2026 को पारित आदेश के माध्यम से बघेल को हेट स्पीच से संबंधित सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया था। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों का पालन करते हुए बघेल ने 11.11.2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।

आज प्रकरण की सुनवाई के दौरान बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे के साथ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में सात माह से अधिक की अवधि न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2026 के अनुपालन में सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बघेल के विरुद्ध उक्त 14 प्रकरणों के अतिरिक्त 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों में आपराधिक पूर्ववृत्त हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से यह भी इंगित किया गया कि तीन माह की अस्थायी जमानत/पैरोल की अवधि समाप्त होने के बावजूद बघेल द्वारा तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अमित बघेल को सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वतंत्रता भी प्रदान की है कि यदि बघेल द्वारा जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य शासन उनकी जमानत निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पीएम स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को मिलेंगे चार राष्ट्रीय पुरस्कार

■ **नई दिल्ली में स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 का आयोजन**

रायपुर। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को चार पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का चयन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए किया गया है। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल 20 नवम्बर को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा संबंधित निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की टीम ये पुरस्कार ग्रहण करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन विभाग और तीनों नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गौरव और प्रसन्नता का विषय है।

राज्य के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन नगरीय निकायों के बेहतर कार्यों और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की इस महत्वाकांक्षी योजना से छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल रहे हैं। यह सम्मान हमारे नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

महादेव सट्टा ऐप मामले में फरार अनिल और विशाल के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रायपुर की विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। दोनों के फरार होने के बीच ईडी ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी अदालत में आवेदन पेश किया है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। विशाल आहुजा के सगे भाई धीरज आहुजा ने इसी विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।



जांच एजेंसी के मुताबिक, आहुजा बंधुओं की भूमिका महादेव ऐप के प्रमोटरों और उनसे जुड़े लोगों की हवाई टिकट बुकिंग के कारोबार से जुड़ी रही है। इस कार्रवाई के बाद महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच एक बार फिर चर्चा में आ गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी लंबे समय से आरोपियों और उनसे जुड़े कारोबार की जांच कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। गैर-जमानती वारंट जारी होने का मतलब है कि संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा सकता है। वहीं, ईडी ने दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी आवेदन दिया है। अब इस मामले में अदालत की आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। जांच एजेंसी की कार्रवाई का उद्देश्य मामले में फरार आरोपियों की भूमिका और कथित वित्तीय लेनदेन की जांच को आगे बढ़ाना है।

इस मामले में विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा की ओर से भी कानूनी कदम उठाया गया है। धीरज ने रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ईडी की जांच में धीरज और विशाल आहुजा की भूमिका टिकट बुकिंग के कारोबार से जुड़ी बताई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों भोपाल स्थित रैपिड ट्रैवल्स नाम की कंपनी का संचालन करते थे। यह कंपनी महादेव ऐप के प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और कारोबारी सहयोगियों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट बुक करती थी। अब धीरज की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत का रुख भी इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगा।

कृषि विवि में राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला 26 एवं 27 नवंबर को

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 26 एवं 27 नवंबर को स्वामी विवेकानन्द सभागार, कृषि महाविद्यालय, रायपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लगभग 250-300 किसान एवं महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य सहित मध्यप्रदेश के 27, उत्तरप्रदेश के 22 तथा उड़ीसा के 09 किसान भाग लेंगे। इसके अलावा बागवानी, मत्स्य, कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल किए जाने के बाद प्रदेश में मखाना उत्पादन के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश में 133.862 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती की जा रही है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)
Office Email ID, eewrckn@cgwrd.in / Fax & Ph.No. 07743-263628

क्रमांक 4110/व.ले.लि. छुईखदान दिनांक 13/10/2026

निविदा निरस्तीकरण आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक 15/व.ले.लि./2025-26, दिनांक 02.02.2026, सिस्टम टेंडर नंबर 184680 प्रथम आमंत्रण खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखंड छुईखदान अंतर्गत् कांशीनाला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर आर.डी. 0 मी. से आर.डी. 2845 मी. तक जीर्णोद्धार एवं सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग का कार्य साथ ही 10 नग इनलेट, 01 नग इस्केप, 05 नग व्ही.आर.बी., 02 नग फाल का निर्माण कार्य एवं कुलाबा पाईप फिक्सिंग कार्य का न्यूनतम निविदा दर स्वीकृति पश्चात् ठेकेदार अनुबंध हेतु उपस्थित नहीं हुये। इस कारण उक्त निविदा निरस्त किया जाता है।

G. NO. 252606421

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग छुईखदान
जिला -खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई(छ.ग.)

जी-262704572/6

आत्मकथा: अल्पसंख्यक के साथ विशेष छवि बनाने की कोशिश

अवधेश कुमार

सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक या आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के प्रकाशन के पूर्व साक्षात्कारों में जो कुछ कहा था उनके संदर्भ में यह मानना सही होगा कि पुस्तक को केवल लोकप्रिय बनाने नहीं बल्कि अपनी दृष्टि से वर्तमान कांग्रेस की दिशा-दशा, रीति-नीति के अंतर्गत सुनियोजित रणनीति के तहत सारी बातें कही गईं। इसे प्रकाशन के पूर्व ही विवादित बना दिया गया था। एक समाचार पत्र ने लिखा कि 'पेंगुइन रैंडम हाऊस इंडिया' ने इस किताब के कुछ हिस्सों विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आर.एस.एस. और चीन से जुड़े मामलों में बदलाव या पैराग्राफ हटाने की मांग की थी जिसे सोनिया गांधी ने मना कर दिया। कांग्रेस ने तुरंत आरोप लगा दिया कि सरकार ने उसके कुछ अंश के प्रकाशन की अनुमति नहीं दी। पेंगुइन ने खंडन किया कि लेखक द्वारा बदलाव अस्वीकार करने के कारण किताब रोकी गई है। तो यह जांच का विषय है कि कोई अंश हटाने के लिए कहा ही नहीं गया तो इतना गहरा विवाद पैदा कैसे हो गया? उनके साक्षात्कार के दो अंश बाबरी विध्वंस और आपातकाल पर दिए बयान सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद में रहे और पुस्तक में भी वही बातें थोड़े विस्तार से हैं। यहां चर्चा बाबरी विध्वंस पर: पुस्तक के मुताबिक ही ब्रिटिश अखबार गार्जियन को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि जब टैलीविजन पर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की तस्वीरें देखीं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह रो पड़ी थीं। उन्हें तभी अहसास हो गया था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों द्वारा बनाए गए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लडऩी होगी। वैसे उन्होंने भाजपा के उभार के लिए कट्टर हिंदुत्व जैसे शब्द का प्रयोग कर उस राजनीति को यहां तक आने के लिए कांग्रेस की विफलताओं और लापरवाही की चर्चा भी की। सोनिया के मुताबिक कांग्रेस कई मामलों में जरूरत से ज्यादा निश्चिंत रही और उसका रवैया भी ढीला था। 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस के समय केंद्र में स्वर्गीय नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। स्पष्ट है कि उन्होंने राव को ही जिम्मेदार ठहराया है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 1999 में पहला चुनाव कांग्रेस ने लड़ा और इतिहास की सबसे कम 114 सीटों पर पार्टी क्यों सिमट गई? भाजपा 6 दिसंबर, 1992 के बाद श्रीराम मंदिर पर पहले की तरह आक्रामक भी नहीं थी। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक सतह पर पार्टी के सर्वमान्य नेता बन चुके थे। सोनिया गांधी ने तब उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग को लोकसभा सत्र में शामिल कर एक वोट से वाजपेयी सरकार को गिराने में भूमिका निभाई और स्वयं राष्ट्रपति के पास जाकर 272 सांसदों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी किया। पर्याप्त समर्थन के अभाव में सरकार नहीं बन सकी। फिर वह किसकी नाकामी और लापरवाही की बात कर रही हैं? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2014 में 44, 2019 में 52 और तीसरे चुनाव 2024 में अभी तक 99 सीटों तक क्यों सिमटी रही? इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा? लगातार 2014 से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस के वर्तमान रणनीतिकारों ने निष्कर्ष निकाला कि उनका मुस्लिम वोट तो गया ही, हिंदू वोट भी चला गया। इसलिए मुस्लिम वोट सुदृढ़ करो, फिर वामपंथियों, समाजवादियों और भाजपा विरोधियों को मिलाकर इतना वोट हो सकता है कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकेंगे और स्वयं को देश और विदेश में सेक्युलरवाद के रक्षक के रूप में उभार भी पाएंगे।

आसियान मंच: भारत का दबदबा, मोदी की कूटनीतिक गूंज

ललित गर्ग



किसी देश का वैश्विक प्रभाव केवल उसकी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता या जनसंख्या से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि विश्व की महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसकी बात को कितनी गंभीरता से सुनती हैं। आज भारत इसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों के संगठन आसियान का भारत सदस्य नहीं है, फिर भी उसके सर्वोच्च सम्मेलनों में भारत की उपस्थिति जिस सम्मान और अपेक्षा के साथ होती है, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का महत्वपूर्ण संकेत है। हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुए 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी ने इस बदलती तस्वीर को और स्पष्ट किया है। यह दृश्य अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान की भविष्य-चर्चा में भारत को अलग रखकर क्षेत्रीय समीकरणों की कल्पना करना कठिन होता जा रहा है। यही भारत की कूटनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 1991 की 'लुक ईस्ट' नीति से शुरू हुई यात्रा 2014 में 'एक्ट ईस्ट' नीति और अब व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टि तक पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के केंद्र में बताया है।

आसियान केवल भौगोलिक समूह नहीं है। यह आर्थिक शक्ति, समुद्री मार्गों, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और हिंद-प्रशांत की रणनीतिक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और तिमोर-लेस्ते जैसे देश भारत के लिए व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक संपर्क की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मनीला में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और आसियान को प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग को आधार बनाकर शांति, स्थिरता और विकास का वातावरण तैयार करना चाहिए। उन्होंने मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और आसियान की एकता तथा केंद्रीयता को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह केवल कूटनीतिक भाषा नहीं है। इसके पीछे भारत की दीर्घकालीन रणनीति है-ऐसा हिंद-प्रशांत जिसमें किसी एक शक्ति का वर्चस्व न हो, छोटे देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की जगह मिले और समुद्री मार्ग खुले रहें।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि उन्होंने भारत को केवल 'बड़ा बाजार' या 'उभरती अर्थव्यवस्था' के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मनीला में इसका प्रमाण अनेक द्विपक्षीय मुलाकातों में दिखाई दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मोदी ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेल, वित्तीय तकनीक तथा व्यापार और निवेश में सहयोग की प्रगति पर चर्चा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ डिजिटल क्षेत्र, कौशल, संपर्क, स्वास्थ्य, रक्षा-सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की समीक्षा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। मोदी की विदेश नीति का संदेश साफ है-भारत संबंधों का केवल दर्शक नहीं, बल्कि संबंधों की नई संरचना का सक्रिय निर्माता बनना चाहता है।

इस पूरी यात्रा में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की राजनीतिक दृष्टि को वैश्विक कूटनीतिक संवाद में ठोस स्वरूप देने में जयशंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे केवल विदेश मंत्रालय के प्रशासक नहीं, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था को समझने वाले रणनीतिक चिंतक के रूप में भारत की विदेश नीति का प्रभावी चेहरा बने हैं। भारत की विदेश नीति में आज एक साथ अमेरिका, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने की क्षमता दिखाई देती है। यह संतुलन किसी एक खेमे में जाने के बजाय भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंधों को आकार देने की नीति को दर्शाता है। जयशंकर की कूटनीति का मूल संदेश भी यही रहा है कि भारत किसी शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों और अपनी सभ्यतागत दृष्टि के आधार पर विश्व से संबंध बनाएगा। प्रधानमंत्री की राजनीतिक सक्रियता और विदेश मंत्री की रणनीतिक कूटनीति का यह संयोजन भारत की विदेश नीति को अधिक प्रभावशाली बना रहा है।

मनीला सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने भी इस यात्रा को विशेष महत्व दिया। 17 नवंबर को मनीला में पहली बार क्वाड नेताओं का शिखर-स्तरीय संवाद हुआ, जिसमें मोदी, ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज शामिल हुए। इस घटनाक्रम का संदेश बहुत व्यापक है। भारत एक ओर आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत की रणनीतिक संरचना को भी मजबूत कर रहा है। इसका अर्थ किसी देश के विरुद्ध मोर्चेबंदी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति शृंखलाओं, महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में साझेदारी को बढ़ाना है। यहां मोदी की विदेश नीति का एक नया आयाम दिखाई देता है-भारत अब शक्ति-संतुलन का निष्क्रिय हिस्सा नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला केंद्र बनना चाहता है।

आसियान देशों के लिए चीन एक बड़ा आर्थिक साझेदार है, लेकिन उसके साथ समुद्री और रणनीतिक विवाद भी हैं। दक्षिण चीन सागर में तनाव, आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय प्रभाव की प्रतिस्पर्धा के बीच आसियान देश किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहते। यही भारत के लिए बड़ा अवसर है। भारत को चीन का विकल्प बनने की जल्दबाजी करने के बजाय विश्वसनीय विकल्प बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए व्यापार घाटे को कम करना, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना, आपूर्ति शृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत-आसियान संपर्क परियोजनाओं को तेजी देना आवश्यक है। मनीला में घोषित समुद्री सहयोग योजना, साइबर प्रशिक्षण, अंतरिक्ष सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, युवाओं और स्टार्ट-अप सहयोग तथा नालंदा में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जैसी पहलें इसी नई दिशा की ओर संकेत करती हैं।

भारत-आसियान संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती व्यापार असंतुलन है। केवल आयात बढ़ाना या बाजार खोलना पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय उद्योग को आसियान के बाजारों में अधिक आक्रामक, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बनानी होगी। मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की ताकत केवल अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी संस्कृति भी है। रामायण की परंपरा से लेकर बौद्ध दर्शन, भारतीय भाषाओं, योग, आयुर्वेद और समुद्री व्यापार की प्राचीन स्मृतियों तक भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराना संबंध है। आज आवश्यकता इस सभ्यतागत पूंजी को आधुनिक आर्थिक और तकनीकी साझेदारी से जोड़ने की है। मनीला सम्मेलन की सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत को आसियान को केवल विदेश नीति की एक इकाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे भारत के आर्थिक, सामरिक और सभ्यतागत पुनर्संपर्क का द्वार बनाना चाहिए। यदि भारत व्यापार, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और संपर्क के साथ संस्कृति, शिक्षा और युवाओं को जोड़ देता है, तो आसियान भारत के लिए केवल एक बाजार नहीं रहेगा, वह भारत के हिंद-प्रशांत भविष्य का स्वाभाविक साझेदार बन सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंचों पर भारत की बात रखते हैं, उसके पीछे वर्षों की कूटनीतिक मेहनत, संस्थागत तैयारी और विदेश मंत्रालय की निरंतर सक्रियता है। आसियान में भारत की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि भारत की आवाज अब केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि उस पर ध्यान भी दिया जाता है।

भारत की विदेश नीति का अगला लक्ष्य केवल विश्व में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य यह होना चाहिए कि विश्व की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका हो। आसियान का मनीला मंच इसी बदलते भारत की तस्वीर सामने रखता है-भारत अब दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने वाला देश नहीं रहा, वह ऐसी शक्ति बन रहा है जिसके साथ दुनिया अपने भविष्य की रणनीति पर विचार करना चाहती है। यही मोदी युग की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि और आने वाले भारत की सबसे बड़ी संभावना है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

वैदिक (हिन्दू) न्याय पर भी दिङ्नाग का बहुत प्रभाव पड़ा, इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता, परन्तु उस देन को ठीक ठीक मापने के लिये भारतीय तर्कशास्त्र की गम्भीर गवेषणा अपेक्षित है। परन्तु न्याय को छोड़कर विशुद्ध दर्शन शास्त्र या ज्ञान सिद्धान्त (epistemo-logy) के क्षेत्र में भी दिङ्नाग की मौलिक देन है।

रूस के विद्वान् लेखक श्चेरवात्स्की ने दो बड़ी जिल्दों में बौद्ध न्यायशास्त्र (Buddhist Logic) नामक ग्रन्थ (जो कि लेनिनग्रेड से प्रकाशित हुआ है) लिखकर दिङ्नाग सम्प्रदाय के दर्शन का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रक्खा है।

आधुनिक युग के पाश्चात्य लेखक होने पर भी श्चेरबात्स्की का स्थान बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्यों में रक्खा जाना चाहिये- इतनी बड़ी उसकी बौद्ध दार्शनिक साहित्य को देन है (देखो पृष्ठ 16 फुटनोट् न0 1)। श्चेरवात्स्की ने हमें बतलाया कि ज्ञान-सिद्धान्त (epistemology) के क्षेत्र में जिस तत्त्व की खोज आधुनिक पाश्चात्य जगत् के सबसे बड़े दार्शनिक इमेन्यूएल काण्ट ने अठारहवीं सदी में की थी, उसकी रूपरेखा दिङ्नाग ने श्वीं सदी में प्रस्तुत कर दी थी।

काण्ट ने पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहिले स्पष्ट रूप से संवेदनात्मक (sensibility) और विचारात्मक (understanding), इन दो प्रकारों का भेद किया था, उसके अनुसार बाह्य जगत् की यथार्थ वस्तु (thing-in-itself) हमारे प्रत्यक्ष से परे की वस्तु है। उसी यथार्थ वस्तु से हमारे अन्दर संवेदनात्मक (sensibility) ज्ञान उत्पन्न होता है, परन्तु संवेदनात्मक ज्ञान आकाररहित है। उसको आकार प्राप्त होता है हमारे विचार के मानसिक प्रत्ययों (categories of understanding) के द्वारा।

क्रमश: ...

देवउठनी एकादशी

लविना शर्मा



देवउठनी एकादशी का पावन पर्व 20 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु का शयनकाल समाप्त हो जाता है और वे अपनी योगनिद्रा से जागृत होकर सृष्टि के संचालन का कार्यभार फिर से संभाल लेते हैं। चातुर्मास के समापन के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ-मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। कई स्थानों पर इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है।

देवउठनी एकादशी की कथा के अनुसार, एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा- प्रभु! आप या तो दिन-रात जागते रहते हैं या फिर जब निद्रा में जाते हैं तो लाखों-करोड़ों वर्षों तक सोते रहते हैं और उस दौरान संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाता है। ऐसे में आप हर साल नियम से कुछ समय की निद्रा लिया करें, जिससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल सके। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले- देवी! तुमने सही कहा। मेरे लगातार जागने से तुम्हें और अन्य देवताओं को विश्राम नहीं मिल पाता। इसलिए तुम्हारे अनुसार अब से मैं हर वर्ष चार महीने के लिए शयन करूंगा। इस समय तुम्हें और सभी देवताओं को आराम मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्पनिद्रा कहलाएगी। जो भक्त इस काल में मेरे शयन की भावना से सेवा करेंगे और मेरे शयन व जागने का उत्सव खुशी से मनाएंगे उनके घर में मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा।

चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या-क्या रहेंगे

ब्रह्म मुहूर्त - 05:01 AM से 05:54 AM
प्रात: सन्ध्या - 05:27 AM से 06:48 AM
अभिजित मुहूर्त - 11:45 AM से 12:28 PM
गोधूलि मुहूर्त - 05:26 PM से 05:52 PM

देवउठनी एकादशी की पूजा विधि

- इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर घर के पूजा स्थल को साफ करें।
- एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें।
- भगवान की प्रतिमा के सामने शालिग्राम शिला रखें और साथ में ही तुलसी का पौधा भी रखें।
- फिर घी का दीप जलाएं और भगवान विष्णु को गंगाजल में स्नान कराएं।
- इसके बाद भगवान को पीले फूल, फल, चंदन, रोली, मिठाई आदि अर्पित करें।
- साथ ही भगवान को शंख, चक्र और गदा भी चढ़ाएं।
- इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
- देवउठनी एकादशी की कथा सुनें और अंत में भगवान की आरती उतारें।
- अगर इस दिन आप तुलसी विवाह करते हैं तो शाम में तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराएं।
- तुलसी विवाह के बाद प्रसाद सभी में बांट दें।

तो क्या ट्रंप के कूटनीतिक मायाजाल में फंस जाएंगे पुतिन और जिनपिंग?

कमलेश पांडे

दुनिया को अपने शब्द जाल में फंसाकर, साम-दाम-दंड-भेद की रणनीति अपनाकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्वप्न संजोए राष्ट्रपति ट्रंप अपने इरादों में कितना कामयाब होंगे, यह तो गुजश्ता वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत की कूटनीतिक स्वायत्ता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई वाली रणनीति से अमेरिका इतना परेशान हो गया कि अब उन्हीं देशों के साथ टेबल की मेज पर बैठा हुआ है, जिनके खिलाफ वह अनवरत षड्यंत्र रचते आया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रूस और चीन की क्या अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी है जो वे वैश्विक रूप से प्रभुत्वहीन हो चुके अमेरिका के साथ मेज साझा कर रहे हैं! कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की कूटनीतिक व रणनीतिक स्वायत्तता से ये दोनों भी भीतर ही भीतर विचलित हो रहे हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दुनियादारी में भारत, अपने समकक्ष देशों यथा- फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा यूरोपीय संघ, मध्यपूर्व के देशों और आशियान देशों के साथ जो समझदारी भरे रिश्ते विकसित कर रहा है, इससे भी अमेरिका, रूस और चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है।

ऐसे में अमेरिका, रूस और चीन के बीच उभरता त्रिकोणीय कूटनीतिक समीकरण केवल तीन महाशक्तियों के नेताओं की मुलाकात का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, रणनीतिक साझेदारियों, आर्थिक हितों और छोटे-बड़े देशों के भरोसे की बड़ी लड़ाई भी दिखाई देती है। ये देश नहीं चाहते कि इनके समानांतर कोई नया देश खड़ा हो और वह उनकी आवाज बने जिनका शोषण करते रहना इनकी नीतिगत फितरत है।

यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ट्रंप, रूस और चीन को आपसी मतभेदों, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और अपने-अपने सहयोगियों के हितों के बीच इस तरह उलझा सकते हैं कि दोनों देशों की विश्वसनीयता प्रभावित होने लगे?

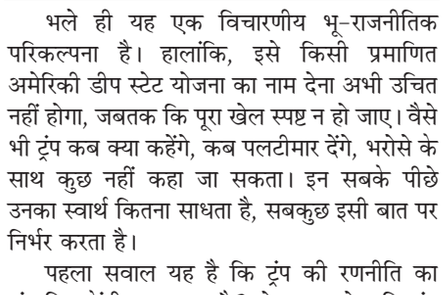

भले ही यह एक विचारणीय भू-राजनीतिक परिकल्पना है। हालांकि, इसे किसी प्रमाणित अमेरिकी डीप स्टेट योजना का नाम देना अभी उचित नहीं होगा, जबतक कि पूरा खेल स्पष्ट न हो जाए। वैसे भी ट्रंप कब क्या कहेंगे, कब पलटीमार देंगे, भरोसे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इन सबके पीछे उनका स्वार्थ कितना साधता है, सबकुछ इसी बात पर निर्भर करता है।

पहला सवाल यह है कि ट्रंप की रणनीति का संभावित केंद्रीय सूत्र क्या है? तो जवाब होगा कि ट्रंप की विदेश नीति में व्यक्तिगत कूटनीति, आर्थिक सौदेबाजी और शक्ति प्रदर्शन को काफी महत्व मिलता है। रूस और चीन के साथ बातचीत के संभावित उद्देश्यों को निम्नलिखित तीन स्तरों पर समझा जा सकता है- एक, रूस को साधना- यूक्रेन युद्ध में समझौते के लिए पुतिन पर कूटनीतिक प्रभाव बनाना और मॉस्को के साथ अमेरिका के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना, ताकि उसे लाभ होता रहे। दो, चीन को साधना- व्यापार, तकनीक, दुर्लभ खनिजों और ताइवान जैसे मुद्दों पर बीजिंग से रियायतें हासिल करना, ताकि उनके उद्योगों के लिए रियायती कच्चा माल मिलता रहे। तीन, दोनों को एक मंच पर लाना- परमाणु हथियार नियंत्रण, ईरान और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर ऐसी बातचीत करना जिसमें अमेरिका अपनी भूमिका केंद्रीय बनाए रखना चाहे। हालांकि, इन सबमें एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी है। वह यह कि चीन और रूस की निकटता अमेरिका की उस पुरानी रणनीति को कमजोर करती है जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर वाशिंगटन अपनी स्थिति मजबूत करता था।

दूसरा सवाल है कि रूस और चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगियों का भरोसा बनाए रखना होगा। खासकर भारत और ईरान आदि जैसे उभरते देशों का। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसप्रकार है- एक, रूस की विश्वसनीयता- यदि पुतिन अमेरिका के साथ किसी बड़े समझौते में यूक्रेन, ईरान या अन्य रणनीतिक साझेदारों के हितों को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं, तो मॉस्को के सहयोगियों के बीच उसकी प्रतिबद्धताओं को लेकर सवाल उठ सकते हैं। दो, चीन की विश्वसनीयता- यदि शी जिनपिंग अमेरिका के साथ किसी समझौते में ताइवान, ईरान या अपने दूसरे रणनीतिक साझेदारों के मुद्दों पर ऐसी रियायत देते हैं जिसे सहयोगी अपने हितों के विरुद्ध समझें, तो चीन की साझेदारी की विश्वसनीयता पर बहस हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। रूस और चीन अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को केवल अमेरिका के साथ बातचीत के आधार पर तय नहीं करते। उनके आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और क्षेत्रीय हित भी इसमें महत्वपूर्ण हैं।

तीसरा सवाल यह है कि क्या ट्रंप दोनों महाशक्तियों को एक-दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहां 1970 के दशक की अमेरिकी त्रिकोणीय कूटनीति याद आती है। तब अमेरिका ने सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर बीजिंग के साथ संबंध बेहतर किए थे। इससे वाशिंगटन को मॉस्को के मुकाबले कूटनीतिक लाभ मिला था। लेकिन 2026 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वह यह कि रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से अधिक मजबूत है। दोनों देश अमेरिकी प्रभुत्व को लेकर कई मुद्दों पर समान चिंताएं रखते हैं। दोनों के आर्थिक और कूटनीतिक हित एक-दूसरे से जुड़े हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी उसके संबंधों में कई बार अनिश्चितता दिखाई देती है। फिर भी आज अमेरिका के लिए रूस और चीन के बीच पुराने जमाने जैसी दरार पैदा करना आसान नहीं है।

चौथा सवाल क्या यही अमेरिकी डीप स्टेट का गेम प्लान है? क्योंकि ट्रंप भी अब इनके सामने घुटने टेक चुके हैं। मिड टर्म चुनावों में अपनी रिपब्लिकन पार्टी की हुई फजीहत से बौखलाए हुए भी हैं। लिहाजा इस सवाल को तीन अलग-अलग अवधारणाओं में समझना जरूरी है- एक, डीप स्टेट- स्थायी प्रशासनिक, सुरक्षा और संस्थागत नेटवर्क का प्रभाव। दो, अमेरिकी रणनीतिक प्रतिष्ठान- विदेश नीति, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थान एवं नीति निर्माता। तीन, ट्रंप की व्यक्तिगत कूटनीति- नेताओं से सीधे बातचीत और द्विपक्षीय सौदेबाजी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों और विदेश नीति से जुड़े स्थायी हित बने रहते हैं। लेकिन यह मान लेना कि इन सभी संस्थानों का कोई एक गुप्त और सर्वसम्मत गेम प्लान है, मौजूदा उपलब्ध प्रमाणों से पुष्ट नहीं होता। इसलिए डीप स्टेट की परिकल्पना को एक राजनीतिक व्याख्या के रूप में देखना चाहिए, स्थापित तथ्य के रूप में नहीं। पांचवां सवाल यह है कि क्या 19 नवंबर की त्रिपक्षीय बैठक के पांच बड़े सवाल का संतुलित जवाब मिलेगा? चूंकि, ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस बैठक से जुड़े पांच महत्वपूर्ण सवाल हैं- एक, क्या यूक्रेन युद्ध के समाधान पर कोई साझा रास्ता निकलेगा? दो, क्या चीन को अमेरिका-रूस परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल करने की कोशिश सफल होगी? तीन, क्या ईरान के मुद्दे पर रूस और चीन अमेरिकी दृष्टिकोण के करीब आएंगे? चार, क्या अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन को कोई राजनीतिक आश्वासन देगा? पांच, क्या तीनों महाशक्तियां अपने सहयोगियों के हितों को ध्यान में रखकर कोई समझौता करेंगी? बैठक के एजेंडे और प्रारूप को लेकर बातचीत जारी थी, क्योंकि तीनों नेताओं के अलग-अलग उद्देश्यों और संभावित हितों को रेखांकित किया है।

आज का इतिहास

1815 यूरोप में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूस, प्रशिया, आस्ट्रिया और इंग्लैंड ने गठबंधन किया।
1829 रूस के निकोलायेव और सेवेस्तोपोल क्षेत्र से यहूदियों को निकाला गया।
1866 अमेरिका के वांशिगटन में हावर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना।
1917 यूक्रेन गणराज्य घोषित हुआ। कलकत्ता (अब कोलकाता) में बोस अनुसंधान संस्थान की स्थापना।
1942 ब्रिटिश सेना ने लीबिया की राजधानी बेनगाजी पर दोबारा कब्जा किया।
1945 जापान का अमेरिका के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण एवं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति।
1955 पॉली उमरीगर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला दोहरा शतक लगाया।
1968 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1981 अफ्रीकी देश बुरुंडी में संविधान अंगीकार किया गया। भास्कर उपग्रह को छोड़ा गया था।
1985 माइक्रोसाफ्ट विंडोज 1.0 जारी हुआ।
1994 अंगोला सरकार और यूनिटा विद्रोहियों के मध्य 19 वर्ष से जारी संघर्ष की समाप्ति के लिए लुसाका में शांति संधि सम्पन्न।
1997 अमेरिकी अंतरिक्ष शटल यान कोलम्बिया फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केन्द्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित।
1998 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जारया का पहला माड्यूल जारी।
2002 अटलांटिक महासागर में स्पेन के तट से क़रीब 150 मील दूर बहामा जा रहा प्रेस्टीज तेल टैंकर डूबा।
2003 तुर्की के इस्ताम्बल में हुए बम विस्फोट में ब्रिटेन के महावाणिज्य दूत सहित 27 लोगों की मृत्यु।
2007 पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय व प्रान्तीय असेंबलियों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।
2008 मालेगाँव धमाके के मामले में गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों पर मकोका लगया गया। राज्यसभा के दो नवनिर्वाचित सदस्यों प्रभाकर कारे तथा बरण मुखर्जी ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। अदन की खाड़ी में अपने व्यावसायिक जहाज़ों की रक्षा के लिए भारत ने गाइडेड मिसाइल युक्त एक विध्वंसक जहाज़ भेजा।
2015 अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमाको में बंधक बनाकर कम से कम 19 लोगों की हत्या की गई।
2016 पीवी सिंधु ने चाइना ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में चीन की सुन यू को तीन गेम तक चले मुकाबले में हराकर पहला सुपर सीरीज ख़िताब अपने नाम किया।

अब मथुरा की बारी! यादव भाजपा के साथ गये तो फंस जाएंगे अखिलेश

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर शुरू हुई सियासत ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद क्या अब मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रही है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे के जरिए भाजपा अखिलेश यादव को ऐसे राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है, जिससे निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा? हम आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव खुद भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी आस्था जताते हुए एक बार कह चुके हैं कि भगवान श्रीकृष्ण उनके सपने में आए थे और उन्होंने बताया था कि अखिलेश की सरकार बनने वाली है। इसलिए अब जब भाजपा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का सवाल उठा रही है, तो अखिलेश के सामने चुनौती है कि वह इस मुद्दे पर अपना रुख क्या रखते हैं। देखना होगा कि कृष्ण के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश जन्मभूमि के मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़े होते हैं या फिर उनकी चुप्पी को भाजपा चुनावी हथियार बनाती है?

हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से बिछती चुनावी बिसात के बीच भाजपा ने मथुरा से ऐसा सियासी संदेश देने की कोशिश की है, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर के लिए मथुरा को चुनना महज एक आयोजन स्थल का चयन नहीं था। यह एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भाजपा के प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल होगा।

केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश यादव को खुली चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर वह भगवान श्रीकृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि की कारसेवा में शामिल हों, भाजपा उन्हें अपने साथ लेकर चलेगी। यह बयान केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सीधे-सीधे अखिलेश यादव की राजनीतिक विश्वसनीयता को चुनौती देने वाला है। भाजपा ने सवाल खड़ा कर दिया है और अब अखिलेश को उसका जवाब देना होगा।

वैसे इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के जातीय और धार्मिक समीकरणों में छिपा है। भाजपा जानती है कि श्रीकृष्ण केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े सामाजिक वर्ग की सांस्कृतिक पहचान भी हैं। यादव समुदाय भगवान श्रीकृष्ण को अपना आराध्य मानता है और अपनी परंपरा को यदुवंश से जोड़ता है। समाजवादी पार्टी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार भी यही यादव मतदाता रहे हैं। ऐसे में भाजपा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को उठाकर एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है।



एक तो भाजपा चाहती है कि हिंदू मतदाताओं के बीच धार्मिक पहचान के आधार पर व्यापक लामबंदी हो। दूसरा, भाजपा का लक्ष्य समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत सामाजिक आधार यानी यादव मतदाताओं के बीच यह सवाल खड़ा करना है कि जब भगवान श्रीकृष्ण उनके आराध्य हैं तो उनके नाम और जन्मभूमि से जुड़े आंदोलन पर अखिलेश यादव का स्पष्ट रुख क्या है?

देखा जाये तो भाजपा की रणनीति का असली खेल यहीं से शुरू होता है। वह चाहती है कि चुनाव की बहस केवल जातीय जनगणना, पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक यानी पीडीए और सामाजिक न्याय तक सीमित न रहे, बल्कि हिंदू पहचान और धार्मिक विरासत का सवाल भी चुनाव के केंद्र में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को गैर-यादव पिछड़ी जातियों, सवर्णों और हिंदू मतदाताओं के व्यापक ध्रुवीकरण का अवसर मिल सकता है। दूसरी ओर, अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से अपनी राजनीति में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। पीडीए रथयात्रा को महाभारत के युद्ध से जोड़ना, खुद को कृष्ण की परंपरा से जोड़ना और सुदामा-कृष्ण की मित्रता के जरिए ब्राह्मण-यादव समीकरण साधने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा है। वह यह संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी राजनीति और सनातन परंपरा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

लेकिन भाजपा ने इसी रणनीति की कमजोर नस पकड़ ली है। अगर अखिलेश श्रीकृष्ण का नाम लेते हैं तो भाजपा उनसे श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर समर्थन मांगेगी। अगर वह मंदिर निर्माण के आंदोलन के साथ खुलकर खड़े होते हैं तो उनकी पीडीए राजनीति और मुस्लिम मतदाताओं के बीच बनाए गए पारंपरिक समीकरण पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और अगर वह इस मुद्दे से दूरी बनाते हैं तो भाजपा उन्हें हिंदू आस्था के सवाल पर घेरने का पूरा मौका हासिल कर लेगी। यानी अखिलेश के सामने भाजपा ने ऐसा सवाल रख दिया है, जिसका कोई भी जवाब उनके लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है।

देखा जाये तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा के सामने एक स्वाभाविक राजनीतिक सवाल था कि अब हिंदुत्व की चुनावी राजनीति का अगला बड़ा प्रतीक क्या होगा? काशी विश्वनाथ धाम के बाद मथुरा का मुद्दा इसी राजनीतिक क्रम में सामने आता है। भाजपा लंबे समय से श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करती रही है। अब 2027 के चुनाव से पहले इसे फिर से आक्रामक तरीके से उठाना बताता है कि पार्टी इस मुद्दे को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाना चाहती है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान का प्रभाव आसपास के इलाकों तक फैला हुआ है। भाजपा इस धार्मिक भूगोल को राजनीतिक भूगोल में बदलने की कोशिश कर सकती है। इस पूरी लड़ाई में अखिलेश यादव की मुश्किल यह है कि भाजपा उन्हें केवल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण के नाम पर राजनीति करने वाले नेता के रूप में जवाब देने के लिए मजबूर करना चाहती है।

इस तरह, मथुरा में अब सवाल यह है कि 2027 के चुनाव में श्रीकृष्ण जन्मभूमि किसकी राजनीतिक ताकत बनेगी और किसके लिए मुश्किलों का सबब? सवाल यह भी है कि क्या भाजपा श्रीकृष्ण के सहारे हिंदू मतों का नया समीकरण तैयार कर पाएगी? क्या यादव मतदाताओं के बीच अखिलेश की एकाधिकार वाली राजनीतिक पकड़ को चुनौती मिलेगी? और क्या पीडीए की सियासत करने वाले अखिलेश को भाजपा उसी महाभारत में उलझा देगी, जिसमें श्रीकृष्ण का नाम लेकर वह खुद अपनी राजनीतिक रणनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं? बहरहाल, उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर भाजपा ने मथुरा से शंखनाद कर दिया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस सियासी चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनते हैं या कोई नया दांव चलते हैं।

पाकिस्तान फिर बिखराव के कगार पर

केसी त्यागी

पाकिस्तान के गठन के वक्त मौलाना आजाद ने जिन्ना को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कहना जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है कि धार्मिक समानता भौगोलिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से भिन्न क्षेत्रों को एकजुट कर सकती है। आज बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा का असंतोष अपने शिखर पर है। सबसे नाजुक हालात बलूचिस्तान में बने हुए हैं। 1947 के बाद पाकिस्तान परियोजना के विरोधी और जिन्ना की नीति की प्रतिक्रिया में, रियासती शासकों के तत्वावधान में बलूच राष्ट्रवाद का उभार हुआ। शासक खान ऑफ कलात (अहमद यार खान) ने 1946 में ही घोषणा की थी कि 'हम स्वतंत्र थे, हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पाकिस्तान या भारत में शामिल होना हमारी इच्छा नहीं है।' 1947 में सरदार कलात ने बलूच स्वतंत्र प्रांत की घोषणा कर जिन्ना को आश्चर्यचकित कर दिया था। पर, 27 मार्च, 1948 को बलपूर्वक इसका पाकिस्तान में विलय कर दिया गया। आज स्थिति यह है कि बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए अपने देश का नाम 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' रख दिया है। इस राष्ट्र का राष्ट्रगान भी जारी कर दिया है और भारत से नई दिल्ली में दूतावास खोलने का अनुरोध किया है। ईरान का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान की जमीन अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है। इस समय अमेरिका ग्वादर बंदरगाह एवं बलूचिस्तान की तटीय रेखा पर प्रभावी होने की फिराक में है। हालांकि, बलूचिस्तान में चीन के हस्तक्षेप के कारण, अमेरिका के लिए प्रभावशाली स्थिति हासिल करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ, पश्तून आंदोलन पाकिस्तानी इतिहास की सबसे प्रमुख, लेकिन विवादास्पद सामाजिक-राजनैतिक घटनाओं में एक है। पश्तूनों की असंतुष्टि ब्रिटिश राज्य की औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था से उपजी है, जिसने सीमा अपराध विनियमन के तहत आदिवासी क्षेत्र पर शासन किया। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सरहदी इलाका है। अफगानिस्तान में तालिबान के पांच साल के शासन में खैबर के अधिकांश इलाकों में इन्हीं का दबदबा है। यों भी खैबर में पाक सरकार का कानून नहीं, तालिबान का शरिया चलता है। अब खैबर पख्तूनख्वा में उग्रवाद पूर्ण विकसित पश्तून विद्रोह में बदल गया है। इसी तरह पीओके में हाल ही में संपन्न चुनाव खून से सन गया। पीओके में पाक फौज कठपुतली सरकार बैठना चाहती है। एक जमाना था, जब आजादी के नाम पर भोले-भाले कश्मीरियों को भड़काया जाता था, वही दांव अब पीओके के मामले में उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने क्षेत्र में बढ़ती हिंसा की खबरों पर चिंता जताते हुए घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने और संयम बरतने की अपील की। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सभी क्षेत्र, जिनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। पाकिस्तान में सिंध देश की मांग पुरानी है। इस आंदोलन की उत्पत्ति 1950 के दशक में विवादित 'वन यूनिट प्लान' के तहत पाकिस्तान की राजनीति के केंद्रीकरण से हुई। इसमें सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तानी पंजाब और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांतों को एक यूनिट में पुनर्गठित किया गया। केंद्रीकरण का यह निरंकुश दमन 1970 तक जारी रहा, जब याह्या खान के नेतृत्व में सेना ने सत्ता संभाली। इससे सिंध के लोगों में व्यापक आक्रोश फैल गया और क्षेत्र में स्वायत्तता और फेडरेलिज्म की मांग उठने लगी। पंजाब और सिंध के बीच सबसे बड़ा संघर्ष सिंधु नदी के पानी को लेकर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। बांग्लादेश बनने के बाद सिंधी राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा मिली और सिंध के संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण की मांग उठने लगी। पंजाब व सिंध का संघर्ष केवल दो प्रांतों का न होकर पाक की संघीय व्यवस्था, संसाधनों के वितरण, भाषाई पहचान और राजनैतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ चुका है। चीनी और अमेरिकी सामरिक हित भिन्न होने के बावजूद, दोनों की रुचि पाक को एकजुट रखने की है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने कसी कमर

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और संगठन बल के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने में जुट गई है। भाजपा ने युवा, महिला, किसान व गरीब समाज को साधने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याजनाओं की बहार ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा तब और अब के अंतर को बताते हुए जनता के मध्य उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी अब हर उत्सव के दौरान जनमानस को यह बता रहे हैं कि उपद्रव से उत्साह की यात्रा नए उप्र की पहचान बन चुकी है। प्रदेश सरकार वर्तमान समय में जहां अपने संकल्प पत्र को पूर्णता प्रदान करने की ओर अग्रसर है वहीं नये लक्ष्यों का भी संकल्प लिया जा रही है। योगी आदित्यनाथ हिन्दू समाज को एकजुटता प्रदान करने का कोई अवसर नहीं चूक रहे हैं।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल से युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर और हरदोई के 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों के 50 हजार से अधिक युवाओं को टैबलेट दिया। मुख्यमंत्री योगी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची मे दर्ज करवाने की अपील करते हुए उनसे बजरंग बली की तरह अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान भी किया।



साथ ही मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार में 2019 से अभी तक युवाओं के लिए हुए कार्यों की जानकारी देते हुए अगली सरकार में युवाओं के लिए किए जा रहे संकल्पों की झलक भी दिखाई। योगी ने युवाओं से वादा किया कि आगामी 26 जनवरी तक युवाओं को एक लाख नौकरियां और दी जाएंगी। पहले चरण में अभी तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। इनमें इन्फोसिस के सहयोग से अनेक पाठयक्रमों की डिजिटल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई है। इनमें योग से लेकर एआई और डीपटेक जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। युवा साथी ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम और सीएम इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और पीएम मुद्रा सहित केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती अवसर पर यह योजना प्रारंभ की गई थी और दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण देने का संकल्प लिया गया था। आईआईएम लखनऊ से कराए गए अध्ययन में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जा रहे हैं।

इस समय उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा प्रदेश है, जहां 56 से 60 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग की है। देश की राजधानी दिल्ली में नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश भारत सरकार ने झेला था तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद त्याग भी करना पड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल-कालेजों की बदहाली के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी युवाओं को भड़काने का असफल प्रयास किया किंतु प्रदेश सरकार की सतर्कता के कारण अराजक तत्व प्रदेश के युवाओ को भड़काने में नाकाम रहे। प्रदेश सरकार युवाओं को यह भी बता रही है कि 2017 से पूर्व प्रदेश में युवाओं के समक्ष पहचान का संकट था जबकि आज वे गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी यह बात भी अवश्य बताते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अब तक प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आठ हजार लेखपालों और 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है।सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।अगले दस दिनों में 42 हजार होमगार्डों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग, लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। अभी तक शिक्षा विभाग के 3,568 पंचायती राज विभाग के 1,375 खेल कोटे के 470 फ़ोरेंसिक विभाग के 28, पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों और राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के युवाओं को केवल सरकारी नौकरी ही नहीं दी जा रही है अपितु विभिन्न माध्यमों से अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे किंतु आज 25 हजार से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बदलते यूपी मे आज ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अमेठी में ए के -203 राइफल का निर्माण हो रहा है। देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल फोन और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट का निर्माण यूपी में हो रहा है। लखनऊ की एचसीएल इकाई में एक समय केवल 100 कर्मचारी थे आज उनकी संख्या 18 हजार है।

आज का उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा क्योंकि अब प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त व अराजकता मुक्त हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाने के कारण अब निवेशक भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं जिसके कारण युवाओं को रोजगार व नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए विदेश जाने के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। कौशल विकास के भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश सरकार छात्राओं के कल्याण के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का अभियान प्रारंभ करेगी।

वन ब्लॉक व वन पूर्व सैनिक योजना से भी युवाओं को प्रशिक्षण देने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक पूर्व सैनिक को जिम्मेदारी देकर स्थानीय युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निवीर भर्ती की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रदेश सरकार चुनावों की घोषणा के पूर्व अभी अपने तरकश से कुछ और तीर निकाल सकती है। इनमें महिलाओं के कल्याण के लिए भी बड़ी योजना आने की सम्भावना है। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार अपने मतदाता को बांध कर रखने के लिए कल्याण योजनाओं को अधिकतम विस्तार देने का प्रयास करेगी।

महाशक्तियों की मेज पर तय होगी दुनिया की नई तकदीर!

नीरज कुमार दुबे

दुनिया के इतिहास में एक बार फिर ऐसा क्षण आने जा रहा है, जब तीन महाशक्तियों के नेता एक साथ बैठकर वैश्विक सत्ता संतुलन की नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को इसी वजह से याल्टा 2.0 कहा जा रहा है। यह महज तीन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश है जिसमें यूक्रेन से लेकर ताइवान, ईरान से लेकर हिंद-प्रशांत और परमाणु हथियारों से लेकर विश्व व्यापार तक के भविष्य पर फैसला हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन मिलकर दुनिया को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या छोटे देशों की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्र विदेश नीति तीन महाशक्तियों की सौदेबाजी की भेंट चढ़ सकती है? साथ ही क्या ट्रंप अपने दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें ऐसी कूटनीतिक चाल में फंसाने जा रहे हैं, जिसका असली निशाना चीन और रूस दोनों होंगे?

देखा जाये तो याल्टा 2.0 को समझने के लिए 1945 के इतिहास में लौटना जरूरी है। हम आपको याद दिला दें कि 4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया के याल्टा में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन एक साथ बैठे थे। उस समय



द्वितीय विश्वयुद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप का राजनीतिक नक्शा कैसा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। उस समय तीनों नेताओं ने जर्मनी के भविष्य, पूर्वी यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते किए थे। जर्मनी और बर्लिन को मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था बनी। सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में व्यापक प्रभाव मिला। पोलैंड के भविष्य और एशिया में सोवियत हितों पर भी सहमति बनी। याल्टा सम्मेलन की सबसे विवादास्पद विरासत यह रही थी कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का रास्ता खुला और छोटे देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में उलझ गई। आगे चलकर यही तनाव शीतयुद्ध की बुनियाद बना।

अब 81 साल बाद दुनिया के सामने लगभग वैसी ही परिस्थिति खड़ी दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ बैठे थे, जबकि 2026 में अमेरिका, चीन और रूस की तिकड़ी वैश्विक शक्ति संतुलन पर चर्चा करने जा रही है। देखा जाये तो इस बैठक का सबसे गंभीर पहलू यूक्रेन युद्ध है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ऐसा समझौता हो, जिससे रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों और रणनीतिक हितों पर बढ़त मिल सके। उनकी कोशिश यह भी हो सकती है कि यूक्रेन और यूरोप को बातचीत के निर्णायक मंच से बाहर रखा जाए। यही वह स्थिति है जिससे यूरोप और कीव चिंतित हैं। यदि अमेरिका और रूस यूक्रेन के भविष्य पर आपसी समझौता करते हैं, तो यह 1945 के याल्टा की याद दिलाएगा, जब पूर्वी यूरोप की नियति तय करने में वहां के देशों की भूमिका सीमित रह गई थी।

वहीं ट्रंप के सामने भी राजनीतिक चुनौती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी कूटनीतिक सफलता दिखानी है। लेकिन क्या वह पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर पाएंगे या रूस को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर वैधता हासिल करने का अवसर मिलेगा? यही इस बैठक की असली परीक्षा होगी। साथ ही ट्रंप की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा चीन को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की बातचीत में शामिल करना है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि नई संधि में चीन भी शामिल हो। लेकिन जिनपिंग इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। अमेरिका और रूस के पास चीन की तुलना में कई गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। बीजिंग का मानना है कि पहले दोनों बड़ी परमाणु शक्तियां अपने हथियार कम करें, उसके बाद चीन को समान प्रतिबंधों में शामिल करने की बात हो। इसलिए ट्रंप का परमाणु प्रस्ताव चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने का हथियार भी है।

इसके अलावा, ट्रंप की मनीला यात्रा और वहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को चुनौती देने वाली कूटनीतिक गतिविधियां इस बैठक को और दिलचस्प बनाती हैं। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप उसी चीन की धरती पर जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकर वैश्विक समझौते की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनपिंग और पुतिन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से काफी मजबूत है। आज दोनों नेताओं की अलग से हो रही बैठक भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रूस को चीन का आर्थिक सहयोग चाहिए और चीन को रूस की ऊर्जा तथा सामरिक साझेदारी।

साथ ही याल्टा 2.0 का असली खतरा यही है कि कहीं दुनिया के छोटे और मध्यम देश फिर से महाशक्तियों की सौदेबाजी के मोहरे न बन जाएं। 1945 में याल्टा ने शीतयुद्ध की जमीन तैयार की थी। 2026 का शेनझेन सम्मेलन अगर किसी नए वैश्विक शक्ति विभाजन की शुरुआत करता है, तो उसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दे सकता है।

बहरहाल, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीनों नेता दुनिया को बांटने का कोई समझौता करने जा रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात केवल कूटनीतिक तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इस बैठक से कौन अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करके निकलता है और कौन दूसरे की बिछाई बिसात पर मोहरा बन जाता है।

बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की कूटनीतिक भूमिका और बढ़ती प्रासंगिकता

देवेश त्रिपाठी

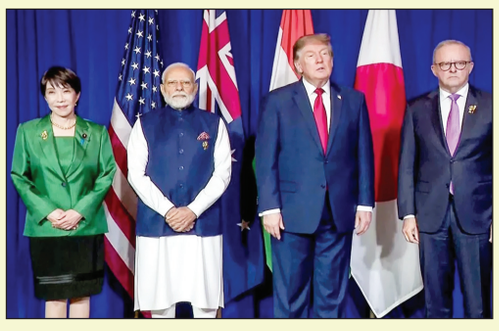

प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा के दौरान संपन्न आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्वाड देशों के नेताओं की बैठक ने बदलती वैश्विक व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखा है। इस कड़ी में 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित मुलाकात भी वैश्विक कूटनीति के नए समीकरणों को समझने का एक और अवसर होगी। आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में भारत की भागीदारी को केवल क्षेत्रीय कूटनीति के एक नियमित आयोजन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया भारत के आर्थिक व सामरिक हितों और समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना उल्लेखनीय है कि भारत व आसियान मिलकर विश्व की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए दोनों के बीच सहयोग को निरंतर मजबूत करना बेहद जरूरी है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच आसियान देशों की सामरिक अहमियत और बढ़ गई है। इस परिप्रेक्ष्य में क्वाड की बैठक भी महत्वपूर्ण रही, जिसमें सदस्य देशों के बीच दुर्लभ खनिजों से संबंधित अहम समझौते हुए। गौरतलब है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित समुद्री परिवेश का पक्षधर है। हालांकि, क्वाड को चीन के विरुद्ध सैन्य गठबंधन के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा, पर यह भी सच है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक व आर्थिक शक्ति इस समूह के गठन व इसकी गतिविधियों की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि रही है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्वाड की यह पहली शिखर बैठक इसलिए भी अहम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन के प्रति नीति में कई बार विरोधाभासी संकेत दिखाई देते हैं। इस बीच, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की कल होने वाली मुलाकात पर भी दुनियाभर की नजरें होंगी। इन देशों के विरोधाभासी हितों व प्राथमिकताओं के मद्देनजर किसी बड़े समझौते या वैश्विक विवादों के समाधान की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बैठक केवल संवाद की एक औपचारिकता बनकर रह जाती है या इससे किसी बड़े कूटनीतिक बदलाव की जमीन भी तैयार होती है। दरअसल, मौजूदा दौर की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी विशेषता है कि देशों के संबंध अब स्थायी मित्रता या शत्रुता के पारंपरिक खांचों में नहीं बंधे हैं। इस बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की प्रासंगिकता केवल इससे नहीं तय होगी कि वह किन देशों के साथ मंच साझा करता है, बल्कि इससे भी होगी कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग में कितना योगदान दे पाता है।



बदलते मौसम भयानक हो सकता है जोड़ों का दर्द, इन आसान तरीकों से अभी से करें बचाव

मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा है। बदलते मौसम में अक्सर जोड़ों में जकड़न, दर्द या सूजन की शिकायत बढ़ जाते हैं। ठंड के मौसम की शुरुआत भी होने लगी है। यह समस्या बदलते मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है। आयुर्वेद में बताया है कि जब शरीर में वात दोष बढ़ता है, तो वह जोड़ों में सूखापन और कठोरता पैदा करता है। इसी वजह से कई लोगों को गठिया या जोड़ों दर्द की पुरानी तकलीफ पैदा हो जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, सर्दी या नमी वाले दिनों में शरीर की ऊष्मा कम हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। जिस वजह से जोड़ों में जकड़न और सूजन बढ़ जाती है। हल्का दर्द अचानक तीव्र हो जाता है।

जोड़ों के दर्द से राहत देंगी ये आयुर्वेदिक उपाय

- जोड़ों के दर्द से आराम पाने के लिए सुबह गुनगुने तिल या सरसों के तेल से जोड़ों की हल्के मालिश करें।
- नहाने से पहले शरीर पर तेल की मालिश करें और रक्त संचार भी बेहतर होता और मांसपेशियां की जकड़न कम हो जाती है।
- सर्दियों के दौरान नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, इस दौरान ठंडे पानी से नहाने बचना जरुरी है।
- भोजन में अदरक, हल्दी, लहसुन और मेथी शामिल करें। इन सभी चीजों में नैचुरल सूजनरोधी गुण होते हैं।
- ज्यादा देर बैठे या खड़े न रहें, बीच-बीच में एक्सरसाइज करें।

नहीं जमती दूध में मोटी मलाई तो ये टिप्स करेंगे आपका काम आसान

हर घर में दूध रोज आता है लेकिन दूध पर जमने वाली मोटी मलाई का भी लोग कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। जितनी मलाई मोटी होगी उतनी ही खाने में भी स्वाद लगेगी। इसके अलावा मलाई से बहुत से लोग घर में घी भी निकालते हैं। दूध की मलाई जितनी मोटी होगी उतना ही घी अच्छी क्वालिटी का होगा। लेकिन बहुत सी महिलाओं की शिकायत होती है कि उनके दूध से मलाई अच्छी तरह से नहीं जम पाती। ऐसे में आपको आज कुछ ऐसे आसान टिप्स बताते हैं जिनके जरिए आप घर के दूध से मोटी मलाई निकाल सकते हैं...

धीमी आंच पर उबालें दूध

ज्यादातर घरों में दूध को मीडियम और फुल फ्लेम पर ही गर्म किया जाता है। परंतु यदि आप दूध में से मोटी मलाई जमाना चाहते हैं तो दूध को 5-10 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबालें।

उबाल आते न बंद करें गैस

दूध में उबाल आते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि गैस को एकदम से बंद न करें। दूध को उबालने के बाद कुछ मिनट के लिए कम आंच पर उबालें। इसके बाद ही गैस बंद करें। इस तरीके से भी दूध में मोटी मलाई जमेगी।

जाली से ढकें दूध

दूध को उबालने के बाद पूरी प्लेट से दूध को ढकने की जगह आप जाली से दूध को ढकें। इस तरीके से दूध आसानी से ठंडा भी होगा और उसमें मलाई भी मोटी जमेगी। पूरी प्लेट से दूध को ढक देने से भाप अच्छे से नहीं निकल पाती जिसके कारण मलाई भी मोटी नहीं जम पाती। ऐसे में आप दूध को जाली से ही ढकें।

सामान्य तापमान

दूध को सामान्य तापमान पर ठंडा करना आवश्यक है। गर्म दूध को फ्रिज में बिल्कुल भी न रखें। ठंडा दूध होने पर बर्तन को बिना हिलाए-जुलाए धीरे से फ्रिज में रखें। इससे दूध में मलाई मोटी जमेगी।

मलाई को निकालकर करें दूध का इस्तेमाल

दूध को जब भी इस्तेमाल करना है तो पहले उसमें जमी पूरी मलाई को निकाल लें। इसके बाद ही दूध का इस्तेमाल करें। इससे दूध में मलाई जमी रहेगी और बार-बार दूध का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं।





मुंह की बदबू से लेकर मसूड़ों की सूजन तक, अमरूद के पत्तों में छिपा है हर समस्या का राज

आज के समय में अधिकतर लोगों को छाले, मसूड़ों में सूजन, दांतों में दर्द और मसूड़ों से खून आने जैसी ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से कई लोग परेशान रहते हैं। हालांकि इस समस्या से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों में से एक और औषधीय गुणों से भरपूर अमरूद के पत्ते लाभकारी माने जाते हैं। अमरूद के पत्तों से बने माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से मुंह की कई समस्याओं से राहत मिल सकती है।

बता दें कि अमरूद के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुए पाए जाते हैं। जोकि मुंह के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से राहत के लिए अमरूद के पत्तों से माउथ वॉश कैसे बनाएं और इससे क्या फायदे मिलते हैं।

अमरूद के पत्तों का माउथवॉश

इसके लिए एक गिलास पानी में 4-5 अमरूद के पते, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 2-3 लौंग डालकर इसको तब तक उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिला दें। अब इस माउथ वॉश से कुल्ला करें।

माउथ वॉश के फायदे

एक्सपर्ट के मुताबिक अमरूद के पत्तों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके पत्तों का माउथवॉश का इस्तेमाल करने से मुंह का स्वास्थ्य दुरुस्त होने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं।

मुंह की बदबू से राहत

अमरूद के पत्तों और लौंग में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इस माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया खत्म होती है और मुंह की बदबू से भी राहत मिलती है। इसका इस्तेमाल करने से फ्रेश फील होता है।

छालों से दे राहत

बता दें कि अमरूद के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ऐसे में इस माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से मुंह के संक्रमण से बचाव होता है और छालों की समस्या से भी राहत मिलती है। वहीं इस माउथ वॉश के इस्तेमाल से मुंह के पीएच को बैलेंस रखने में सहायता मिलती है।

कैविटीज से बचाव

इस नेचुरल माउथ वॉश के इस्तेमाल से दांतों के दर्द को कम करने, कैविटीज से बचाव करने, दांतों के पीलेपन को कम करने और इनको हेल्दी बनाए रखने में सहायता मिलती है।

मसूड़ों की मजबूती

अक्सर लोगों को मसूड़ों में ब्लीडिंग और सूजन होने की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में इस नेचुरल माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से मसूड़ों की सूजन कम होती है। साथ मसूड़ों को टाइट कर मजबूती देने, ब्लीडिंग से बचाव करने और इंफेक्शन से बचाव करने में सहायता मिलती है।

दांतों होंगे हेल्दी

अमरूद के पत्ते, लौंग और नारियल तेल से बना माउथ वॉश से दांतों को मजबूती मिलती है। इससे दर्द और सूजन भी कम होती है। साथ ही इस माउथ वॉश के इस्तेमाल से दांतों को नेचुरली साफ करने में मदद मिलती है।

पुरानी से पुरानी खांसी और जमे कफ को बाहर निकाल देगा ये देसी नुस्खा, सर्दियों में बेहद फायदेमंद



अक्टूबर का महीना खत्म होते-होते ठंड ने दस्तक दे दी है। यह मौसम जितना सुहावना होता है, उतनी ही परेशानियां भी साथ लाता है। खासकर खांसी, जुकाम और सीने में जमे कफ की समस्या लगभग हर घर में देखने को मिलती है। कई बार दवाइयां लेने के बाद भी इन समस्याओं से राहत नहीं मिलती। ऐसे में आयुर्वेदिक और देसी नुस्खे बेहद असरदार साबित हो सकते हैं।

अपनाएं ये देसी नुस्खा

पुरानी खांसी और जमे हुए कफ को निकालने के लिए यह नुस्खा बेहद कारगर है। इसके लिए सबसे पहले एक नींबू को धीमी आंच पर करीब 20 मिनट तक गर्म करें। इसके बाद उसे बीच से काट लें। अब एक चम्मच में आधा चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच अदरक का रस, एक चम्मच शहद और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करें। इसे धीरे-धीरे चाटें। इस घरेलू मिश्रण का म्युकोलिटिक ऐक्शन सीने में जमा हुए कफ को ढीला करता है और पुरानी से पुरानी खांसी से राहत दिलाता है।

सर्दियों में इन बातों का रखें ध्यान

संक्रमण से बचाव

सर्दियों के मौसम में संक्रमण (इंफेक्शन) का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। समय-समय पर हाथ धोते रहें, और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले मास्क पहनें। जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर होती है, उन्हें ठंड के मौसम में खास सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बार-बार खांसी-जुकाम और सर्दी से जुड़ी समस्याएं घेर सकती हैं।

रोज पिएं हल्दी वाला दूध

सर्दियों के मौसम में हर रात सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है। हल्दी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की इम्युनिटी को बूस्ट करते हैं और आपको खांसी, जुकाम तथा गले की खराश जैसी मौसमी समस्याओं से बचाते हैं। यह न केवल शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है, बल्कि सर्द मौसम में गर्माहट भी बनाए रखता है।

पौष्टिक आहार लें

सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन बेहद जरूरी है। अपने दैनिक भोजन में हरी सब्जियां, दालें, मौसमी फल और घर का बना ताजा खाना शामिल करें। इससे शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इस मौसम में जंक फूड, तली-भुनी या बहुत मसालेदार चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये पाचन को प्रभावित कर सकती हैं और सर्दी-जुकाम की समस्या बढ़ा सकती हैं।

यह नुस्खा सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। अगर आपको लगातार खांसी या सीने में दर्द जैसी समस्या है, तो किसी योग्य चिकित्सक या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

रात भर मुंह में रखकर सोएं तुलसी का पत्ता, मिलेंगे गजब स्वास्थ्य लाभ

तुलसी का भारतीय घर में धार्मिक महत्व तो है ही लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक औषधि भी है। आज भी हमारी दादी मां- नानी मां भी सर्दी- खांसी या कोई भी वायरल होने पर तुलसी का काढ़ा आदि पीने की सलाह देती हैं। बता दें तुलसी की पत्तियों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटा- सेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद की मानें तो ये कई बीमारियों का इलाज है।

पाचन तंत्र होता है बेहतर

अगर आपको गैस और एसिडिटी की दिक्कत रहती है, तो रोजाना मुंह में तुलसी के 2 पत्ते रखकर सोएं। इससे पाचन तंत्र स्ट्रांग बनेगा।

तनाव से मुक्ति

तुलसी की पत्तियों में भरपूर मात्रा में अडैप्टोजेन होता है, जो स्ट्रेस लेवल को कम करने में मददगार है। तुलसी की पत्तियां नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं। इसे खाकर सोने से मन शांत होता और बेहद पॉजिटिव महसूस होता है।

सिर दर्द होता है गायब



अगर आपको लगातार सिर में दर्द रहता है और इस वजह से नींद भी नहीं आती है तो अपने मुंह में पत्ते रखकर सोएं। इसमें मौजूद गुण सिर के दर्द को कम करते हैं।

ब्लड शुगर रहता है कंट्रोल में

जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन्हें तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन बढ़ता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।

इम्यूनिटी होता है बूस्ट

तुलसी की पत्तियों में मौजूद विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। रोजाना इसे मुंह में रखकर सोने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

सर्दी- जुकाम से मिलती है राहत

तुलसी की पत्तियों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो वायरस का जड़ से खत्म कर देते हैं। रातभर इन्हें मुंह में रखकर सोने से सर्दी-जुकाम से राहत मिलती है।

चेहरे पर कैसे लगाएं मुल्तानी मिट्टी? इस तरह मिलेंगे बेहतर रिजल्ट्स

चेहरे की खूबसूरती और नेचुरल ग्लो बढ़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कई लगो करते हैं। यह स्किन से ऑयल और गंदगी हटाकर उसे साफ, मुलायम और फ्रेश बनाती है।

चेहरे पर चमक बनाए रखने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। कई लोग मार्केट से महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स खरीदकर उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग घर में ही मौजूद चीजों को लगाते हैं। ऐसे में अगर आप भी स्किन को मुलायम और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी को चेहरे पर लगाने से कई तरह के फायदे होते हैं। इसका फेस पैक स्किन को गहराई से साफ करता है और चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल भी करता है।



हालांकि, कई बार लोग इसका गलत तरीके से उपयोग कर लेते हैं, जिससे स्किन ड्राई या रफ हो सकती है। अगर आप भी अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने का तरीका

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए सबसे पहले चेहरे को सही से साफ कर लें, ताकि स्किन के पोर्स खुल जाएं और गंदगी साफ हो सके। अब आप एक बाउल में दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें अपनी स्किन टाइप के मुताबिक कुछ चीजें मिला लें। आप इसके लिए किसी डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं।

अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ दूध या गुलाबजल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो इसके साथ आप नींबू का रस या एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। वहीं, नॉर्मल स्किन के लिए साफ पानी या दही बेहतर होता है।

चेहरे पर कैसे लगाएं मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तैयार करने के बाद आप किसी मुलायम ब्रश या फिर उंगलियों की मदद से इसे चेहरे पर समान रूप से लगाएं। अब इसे करीब 10-15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद इसे साफ पानी से धो लें। चेहरे से फेस पैक हटाने के बाद कोई हल्का मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर कसा तंज



गोरखपुर। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल जेसीबी की चपेट में आए बच्चे की मौत पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन को निर्देश दिया है कि सड़कों पर अराजकता फैलाने वाले उपद्रवियों को चिह्नित कर ऐसी सजा दिलाई जाए, जिसे उनकी पीढ़ियां याद रखें। उन्होंने कहा कि झंगहा से पढ़ाई के लिए आए 12-13 वर्षीय मासूम छात्र का क्या कसूर था, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना पर संवेदना तक नहीं जताई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर किसी ने माफियागिरी करने की कोशिश की तो उसे मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का मतलब गुंडागर्दी, अराजकता, दंगे और कर्फ्यू है। माफिया उनके सहयोगी रहे हैं और उन्होंने हमेशा जनता के साथ विश्वासघात किया है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के काफिले पर हमला



कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों के एक समूह ने उनकी कार और काफिले पर पत्थर तथा अंडे फेंके। उन्होंने आरोप लगाया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही। कृष्णानगर की सांसद ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर सिलसिलेवार किए कई पोस्ट में दावा किया कि 80-90 भाजपा समर्थक गोबरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में उन पर हमला करने के लिए जमा हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को इस जमावड़े की पहले से जानकारी थी। मोइत्रा ने पोस्ट किया, ''पश्चिम बंगाल पुलिस, पुलिस महानिदेशक और कृष्णानगर पुलिस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के तहत मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है।

शाइना एनसी के खिलाफ सड़क पर उतरा उद्धव गुट



मुंबई। मुंबई में गुरूवार को शिवसेना (यूबीटी) के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिवसेना नेता शाइना एनसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन पर एक कार्यक्रम के दौरान दिवंगत बाल ठाकरे की तस्वीर फाड़ने का आरोप है। प्रदर्शन के बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दादर स्थित शिवसेना (यूबीटी) के मुख्यालय सेना भवन के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने शाइना एनसी के खिलाफ नारेबाजी की और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान शिवसेना (यूबीटी) के कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया।

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ईडी की याचिका खारिज



नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बृहस्पतिवार को बरकरार रखते हुए उनकी जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने ईडी की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया थीं और अंतिम निर्णय पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पीठ ने अपने आदेश में कहा, यह अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और मामले पर अंतिम निर्णय लेते समय उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खान को धन शोधन के मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी ने उन्हें 31 अक्टूबर को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे।

मोहन भागवत के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल



इम्फाल। मणिपुर में कांग्रेस विधायक दल के नेता केशम मेघचंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत का मौजूदा दौरा इस हिंसाग्रस्त राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में कोई ठोस योगदान दे पाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर को अब एक बार फिर आश्वासन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे ''स्थायी शांति, सुरक्षा, पुनर्वास, जवाबदेही और एक विश्वसनीय राजनीतिक रोडमैप की आवश्यकता है।'' भागवत बुधवार दोपहर तीन दिवसीय दौरे पर इंफाल पहुंचे। इस दौरान वह राज्य में संगठन की गतिविधियों और सामाजिक पहलों की समीक्षा करेंगे। संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि वह आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत राज्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का भी आकलन करेंगे। केशम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''मणिपुर को शांति चाहिए, केवल संगठनात्मक बैठकें नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 18 से 20 नवंबर तक मणिपुर दौरा हमारे राज्य में जारी संकट को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।''

प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में फिक्की की 100वीं वार्षिक महासभा और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया

पीएम मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों का दिया करारा जवाब



नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ मंत्रिपरिषद की बैठक में देश को बचत, संयम, स्वस्थ जीवनशैली और नशामुक्ति का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के शताब्दी समारोह में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां गिनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की संस्कृति 'खाओ, पियो और मौज करो' की नहीं, बल्कि बचत, अनुशासन और भविष्य के लिए संसाधन जुटाने की रही है। उन्होंने गरीबी और नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता के बाद नशे की समस्या को अगली बड़ी राष्ट्रीय चुनौती बताते हुए इसके खिलाफ सामूहिक अभियान चलाने का आह्वान किया। वहीं फिक्की के मंच से उन्होंने विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की लगभग 7 प्रतिशत विकास दर, रिकॉर्ड निर्यात और वैश्विक संस्थाओं के बढ़ते भरोसे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के भारत को 'इकोनॉमिक डिजास्टर' बताने वाले बयान को भी आंकड़ों के जरिए चुनौती दी। 24 घंटे के भीतर सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और देश की आर्थिक प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री के इन दोनों संदेशों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक विकास के साथ सामाजिक अनुशासन, नागरिकों की सेहत और आत्मनिर्भरता को भी समान महत्व दे रही है।

जहां तक मंत्रिपरिषद की बैठक की बात है तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों से बचत की आदत को प्रोत्साहित करने की अपील की। दरअसल इसके पीछे उनकी चिंता यह है कि जो परिवार कठिन परिश्रम और सरकारी योजनाओं के सहारे गरीबी से बाहर निकले हैं, वे अनियंत्रित खर्च और गैरजरूरी उपभोग के कारण दोबारा आर्थिक संकट में न फंस जाएं। सरकार चाहती है कि लोगों की आमदनी बढ़ने के साथ उनकी बचत भी बढ़े, ताकि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हों और देश में निवेश की क्षमता का विस्तार हो।

साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने नशे की समस्या को अगली बड़ी राष्ट्रीय चुनौती के रूप में सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस सामूहिक इच्छाशक्ति से भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की और वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद के खतरे को कमजोर किया, उसी संकल्प के साथ नशे की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसमें पूरे सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठनों, परिवारों और आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। इसे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का विषय बनाना होगा, क्योंकि नशे का सबसे बड़ा नुकसान देश की युवा पीढ़ी को उठाना पड़ता है।

इस संदेश में स्वास्थ्य और फिटनेस का पहलू भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता ऐसी जीवनशैली को प्रोत्साहित करने की है जिसमें युवा नशे से दूर रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें तथा अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाएं।

हम आपको बता दें कि 18 नवंबर को फिलीपींस से लौटने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। बैठक में 11 केंद्रीय सचिवों ने अलग-अलग विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। इनमें वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आवास और मत्स्य पालन सहित कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल थे। बैठक में गरीबी उन्मूलन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई। गृह सचिव गोविंद मोहन ने नक्सलमुक्त भारत को लेकर प्रस्तुति दी और इस खतरे की दोबारा वापसी रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों तथा भविष्य की रणनीति की जानकारी दी। साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के उपाय भी चर्चा का हिस्सा रहे। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, उनका जमीन पर प्रभाव दिखाई देना चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय बैठकों और विदेश यात्राओं के बाद वह घरेलू प्रशासनिक प्राथमिकताओं की समीक्षा में देर नहीं करते। मनीला यात्रा से लौटने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना इसी कार्यशैली का उदाहरण है। दरअसल, इससे मंत्रियों और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश जाता है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के साथ-साथ घरेलू विकास, सरकारी योजनाओं की गति और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी लगातार निगरानी रखनी होगी।

इसके अलावा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के शताब्दी समारोह में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को सामने रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'इकोनॉमिक डिजास्टर' वाले बयान का आंकड़ों के साथ जवाब दिया। भारत मंडपम में आयोजित फिक्की के वार्षिक अधिवेशन और शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने अक्टूबर महीने में भारत के वस्तु निर्यात के लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का भी उल्लेख किया, जो अब तक का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है। मोदी ने कांग्रेस के पुराने शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 1970 के दशक में जब 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया था, तब भारत की आबादी लगभग 50 करोड़ थी। उस समय भी गरीबी समाप्त की जा सकती थी, लेकिन नीतियों में खामी और सही नीयत की कमी रही।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री का यह बयान राहुल गांधी के उस दावे का सीधा राजनीतिक जवाब है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत को 'इकोनॉमिक डिजास्टर' बताया था। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन स्नढ्ढष्टष्टढ्ढ के मंच से प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, निर्यात और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बढ़ते भरोसे के आंकड़े रखकर विपक्ष के आरोपों को चुनौती दी। मोदी ने कहा कि भारत ने एक समय लाइसेंस-कोटा राज और आर्थिक चुनौतियों का दौर देखा है। देश को कभी दुनिया की 'फ्रैजाइल फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत ने मिलकर इस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पीएम मोदी के पोस्ट पर जयराम रमेश का तंज

युवाओं तक पहुंचने की बेताब कोशिश में प्रधानमंत्री



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने एक्स हैंडल पर लोकप्रिय वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (जीटीए)का इस्तेमाल भारत की तरक्की को दिखाने के लिए किया है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा, युवाओं तक पहुंचने की बेताब कोशिश में पीएम ने सोशल मीडिया पर जीटीए 5 और जीटीए 6 गेम की तस्वीरों का सहारा लिया है। याद रहे कि इस वीडियो गेम में दो अपराधियों की कहानी दिखाई गई है। यह कितना उपयुक्त है।

बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें जीटीए 5 और जीटीए 6 के बीच के 13 वर्षों में देश में हुए बदलावों को दिखाया गया है। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, भारत अब एक बिल्कुल नया गेम खेल रहा है। प्रधानमंत्री की इस पोस्ट में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर गरीबी में कमी, सोलर पावर, इंटरनेट और अंतरिक्ष क्षेत्र तक की उपलब्धियों का जिक्र है। पोस्ट में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा गया है।

प्रधानमंत्री की पोस्ट में जीटीए 5 और जीटीए 6 की रिलीज के बीच भारत में आए बदलावों को अलग-अलग तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। पोस्ट में बताया गया है कि पहले दुनिया की फ्रेजाइल फाइव अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल था, लेकिन अब वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुका है।

दरअसल, अगस्त 2013 में मॉर्गन स्टेनली के एक विश्लेषक ने फ्रेजाइल फाइव शब्द का इस्तेमाल किया था। इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्किये शामिल थे। इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भर और वैश्विक आर्थिक बदलावों के प्रति संवेदनशील माना गया था। भारत अब इस समूह में नहीं है।

पीएम मोदी की पोस्ट में पिछले 13 वर्षों में देश में हुए कई बड़े बदलावों को दिखाई गई है। इनमें गरीबी में कमी और स्वच्छता मिशन के पूरा होने का जिक्र भी शामिल है। इसके अलावा देश में सोलर पावर क्षमता में हुई बड़ी बढ़ोतरी को भी उपलब्धि के तौर पर दिखाया गया है। पोस्ट में अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी जिक्र है। इसके मुताबिक, भारत में अब 440 रजिस्टर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं। इसके साथ ही देश में बिजली पहुंचाने के काम में हुई प्रगति को भी दिखाया गया है।

गेमिंग कम्युनिटी से जुड़ने के लिए पोस्ट में इंटरनेट की कीमतों का उदाहरण भी दिया गया है। बताया गया है कि हाई-स्पीड इंटरनेट की कीमत 2013 में जहां 308 रुपये प्रति जीबी थी वहीं अब यह घटकर 7.51 रुपये प्रति जीबी रह गई है। इसके अलावा देश में नक्सलवाद के खत्म होने और भारत के बड़े रक्षा निर्यातक के रूप में उभरने को भी उपलब्धियों की सूची में शामिल किया गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में पांच विकेट पर 243 रन बनाए



वेलिंग्टन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में खेला जा रहा पहले टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में पांच विकेट पर 243 रन बनाए हैं। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। जसप्रीत बुमराह की अगुआई में तेज गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और पहले ही सत्र में न्यूजीलैंड को चार झटके दिए और दूसरे सत्र में उनकी आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। हालांकि, इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े हुए और कीवी टीम को मुश्किल से उबारा।

स्टंप्स के समय निकोल्स 221 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 113 रन और ग्लेन फिलिप्स 182 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत के लिए बुमराह को अब तक तीन विकेट मिले, जबकि अंशुल कंबोज और आकाश दीप ने एक-एक विकेट लिया।

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जसप्रीत बुमराह ने मैच की तीसरी गेंद पर ही टॉम लाथम (0) को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद अंशुल कंबोज ने डेवोन कॉनवे (4) को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। आकाश दीप ने रचिन रवींद्र (15) को पंत के हाथों कैच कराकर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दिया। बुमराह ने डेरिल मिचेल (1) को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। इसके बाद उन्होंने टॉम ब्लंडेल (5) को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर न्यूजीलैंड का स्कोर 70 रन पर पांच विकेट कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की थी जिससे लग रहा था कि आज ही न्यूजीलैंड की पहली पारी सिमट जाएगी। लेकिन दूसरे और तीसरे सत्र में फिलिप्स और निकोल्स पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों पर हावी रहे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स-निफ्टी में जोरदार उछाल, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शानदार रिकवरी देखने को मिली। कारोबार की शुरुआत में गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने जोरदार वापसी की। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से करीब 1,231 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी में भी 376 अंकों से ज्यादा की रिकवरी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 989.94 अंक उछल कर 83,021.75 पर बंद हुआ और निफ्टी 286.35 अंकों की तेजी के साथ 25,514.30 के स्तर पर आ गया। इस तेजी के चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.59 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी मानी जा रही है। बाजार में तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों की खरीदारी अहम वजह रही। बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,866.78 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

नहीं लगेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज

नई दिल्ली। यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों और डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले दुकानदारों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमआरडी) यानी पेमेंट प्रोसेसिंग फीस लागू करने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस फैसले को लेकर जल्दबाजी में नहीं है और इसे 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है। अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। व्यापारिक संगठनों के विरोध को इस देरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। फिलहाल भारत में यूपीआई के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा आमतौर पर मुफ्त है लेकिन सितंबर में सामने आए प्रस्ताव के मुताबिक, 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी एमआरडी लगाने की योजना है।

महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ खुला

नई दिल्ली। महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित आईपीओ गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ के लिए निवेशक आज से पैसे लगा सकते हैं। इधर, ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहे हैं। आईपीओ खुलने से पहले हुए एंकर राउंड में कुल 53 एंकर निवेशकों ने 2,295.24 करोड़ रुपये लगा दिए हैं। महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरकर सिर्फ 3.1 रुपये पर आ गया है। हालांकि, निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीएमपी एक अनौपचारिक मार्केट इंडिकेटर है और लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है। असल लिस्टिंग प्राइस आखिर में मार्केट की स्थितियों और लिस्टिंग के दिन निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा।

एंथ्रोपिक ने आईपीओ के लिए मूल्य तय किया

ओकलैंड। कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एंथ्रोपिक ने बुधवार को अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 83 डॉलर प्रति शेयर का मूल्य तय किया। इससे कंपनी का मूल्यांकन 1,500 अरब डॉलर हो गया है। यह वॉल स्ट्रीट (अमेरिकी बाजार) का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। कंपनी ने शुरुआत में प्रति शेयर 70 से 78 डॉलर का मूल्य दायरा तय किया था। इससे अधिक मूल्य पर शेयर की पेशकश से एआई कंपनियों के शेयर में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी का पता चलता है। एंथ्रोपिक के अनुसार, आईपीओ में कुल 98 करोड़ शेयर पेश किए गए हैं। इनमें से करीब 95.6 करोड़ शेयर कंपनी और शेष मौजूदा शेयरधारकों की ओर से बेचे जा रहे हैं। इस पेशकश से कुल 81 अरब डॉलर जुटाए जा रहे हैं।

क्या सच में आर्थिक आपदा की कगार पर है भारत?

अभिनय आकाश

अरहर की दाल 140 रुपये, चीनी 60 रुपये, प्याज दोगुना होकर 50 रुपये और फुल क्रीम दूध 76 रुपये लीटर यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ताज़ा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले एक साल में आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। एक तरफ देश के भीतर महंगाई की यह मार है, तो दूसरी तरफ सात समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठकर राहुल गांधी ने एक नया सियासी धमाका कर दिया है। डेड इकोनॉमी के बाद अब उन्होंने भारत को डिजास्टर इकोनॉमी करार दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई महंगाई के ये आंकड़े किसी आर्थिक संकट का इशारा हैं, या फिर वैश्विक एजेंसियों के तेज़ विकास के दावों के बीच यह सिर्फ़ एक सियासी बयानबाज़ी है? कौन है इस महंगाई का असली विलेन और 2027 में आम आदमी को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किल आज मुद्दा आपकी रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों से जुड़ा है, आपकी जेब से जुड़ा है, इसलिए एमआरआई का ये आर्थिक विश्लेषण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

जून 2026 में महंगाई दर 5.3% थी, जो जुलाई में 5.5%, अगस्त में 6%, सितंबर में 7.7% और अक्टूबर में 23 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर यानी 8.9% पर पहुंच गई। पिछली बार के अनुभव और इस बार के रिकॉर्ड तोड़ एल नीनो को देखते हुए आशंका है कि महंगाई का यह दौर अगले पूरे साल तक खिंच सकता है। हालात डरावने जरूर हैं, लेकिन 2023-24 के मुकाबले इस बार सरकार के पास एक बड़ा सुरक्षा कवच यानी एक प्रोटेक्टिंग लेयर मौजूद है। सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक जरूरी न्यूनतम बफर स्टॉक से 3.3 गुना ज्यादा है। 1 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक,



अकेले चावल का स्टॉक 55.5 मिलियन टन है, जो इस तारीख के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं, 46.3 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक भी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, सरकारी एजेंसियों के पास करीब 3.8 मिलियन टन दालों का भी स्टॉक है, जिसमें 1.6 मिलियन टन चना, 1 मिलियन टन अरहर (तूर) दाल और 1.2 मिलियन टन मूंग, मसूर और उड़द जैसी अन्य दालें शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था को लेकर इस समय दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे जमीनी सवाल हैं। अगर वैश्विक आंकड़ों की बात करें, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एसएंडपी ग्लोबल और मूडीज़ जैसी संस्थाओं ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगभग 6.9% से 7% के आसपास रखा है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ मानी जा रही है। गोल्डमैन सैक्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक की रिपोर्ट्स में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, अस्पताल और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार का ज़िक्र होता है। ये सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, जिनके आकलन वैश्विक आर्थिक मानकों पर आधारित होते हैं।

दूसरी तरफ, विपक्ष और राहुल गांधी देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं जताते रहे हैं और इकोनॉमिक डिजास्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके तर्क का आधार जीडीपी के बड़े आंकड़ों के बजाय बेरोजगारी, महंगाई, आय की असमानता और आम आदमी की घटती क्रय शक्ति जैसे मुद्दे होते हैं। विपक्ष का मानना है कि केवल मैक्रो-इकोनॉमिक ग्रोथ से हर वर्ग का भला नहीं हो रहा है। हालांकि, बहस का मुख्य बिंदु यह बनता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना और विरोध का मंच क्या होना चाहिए। देश के भीतर संसद और सड़कों पर आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब यही बातें विदेशी मंचों से कही जाती हैं, तो उस पर राजनीतिक विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। आलोचकों का मानना है कि विदेशी धरती पर देश की अर्थव्यवस्था को निराशाजनक रूप में पेश करने से निवेशकों के भरोसे और देश की छवि पर असर पड़ सकता है, जबकि विपक्ष इसे वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बताता है।

जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी: साय

मुख्यमंत्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार





रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी गांव में सड़क बनती है, किसी स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी के पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।

लेखा परीक्षा की टिप्पणियां सुधार का अवसर-

मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूती प्रदान करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा सुशासन की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा एक ऐसे आईने की तरह है, जो शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा दिखाती है। उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी हुई राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी किसान की जरूरत या किसी मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

डिजिटल तकनीक से वित्तीय प्रबंधन में बढ़ रही पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और व्यय की प्रभावी निगरानी हो सकेगी।

महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा कि पहले ये लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं।

स्काउटिंग से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सेवाभाव का होता है विकास : खंडेलवाल

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष गजेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में गुरुवार को रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का एक दिवसीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्काउटिंग गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने, संगठनात्मक कार्यों को गति देने तथा स्काउटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सम्मानित किया गया। मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, नई दिल्ली डॉ. के. के.



खंडेलवाल ने कहा कि स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन विद्यार्थियों और युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवाभाव विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

स्काउटिंग गतिविधियां बच्चों एवं युवाओं को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और समाज सेवा की प्रेरणा देने वाला सशक्त आंदोलन है। प्रदेश के विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स की गतिविधियों को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। सेमिनार में स्काउटिंग गतिविधियों के विस्तार, संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा युवाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान स्काउटिंग से जुड़े पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप सक्रिय भूमिका निभाने और सेवा कार्यों में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। समारोह के दौरान स्काउटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 42 पदाधिकारियों एवं सदस्यों को विभिन्न अलंकरण एवं सम्मान प्रदान किए गए। इनमें एक अधिकारी को एलटी (लीडर ट्रेनर), पांच अधिकारियों को एएलटी 2025, दो अधिकारियों को एएलटी 2026 तथा तीन सदस्यों को एचडब्ल्यूबी सम्मान प्रदान किया गया।

राज्यपाल से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने सौजन्य भेंट की । उन्होंने राज्यपाल को आगामी 23 नवंबर 2026 को मानव तस्करी एवं घरेलू हिंसा विषय पर आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।



भनपुरी में अवैध व्यावसायिक निर्माण पर निगम का बुलडोजर

नक्शे के विपरीत बने भवन को किया सीलबंद, बालाजी ओनियन का निर्माण तोड़ा

रायपुर। भनपुरी चौक के पास रिंगरोड में अनुमति के विपरीत पीछे की ओर किए गए अतिरिक्त व्यावसायिक भवन निर्माण को नगर निगम ने तत्काल सीलबंद किया। वहीं बालाजी ओनियन भनपुरी रोड में बिना अनुमति किए गए व्यावसायिक निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 1 नगर निवेश विभाग ने जोन 1 जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा के मार्गनिर्देशन एवं कार्यपालन अभियंता द्रोणी कुमार पैकरा, सहायक अभियंता शरद देशमुख, उपअभियंता अंकिता सोनवर्षा की उपस्थिति में यह कार्रवाई की।



जोन 1 क्षेत्र अंतर्गत भनपुरी चौक रिंगरोड के पास पूनम सिंह अरोरा द्वारा नक्शा स्वीकृति के विपरीत पीछे की ओर अतिरिक्त क्षेत्र में किए गए व्यावसायिक निर्माण को स्थल पर नियमानुसार कार्रवाई कर तत्काल सीलबंद किया गया। नगर निगम जोन 1 नगर निवेश विभाग द्वारा भनपुरी चौक क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए अवैध व्यावसायिक भवन निर्माण पर कार्रवाई करते हुए भनपुरी बालाजी ओनियन के बिना अनुमति व्यावसायिक भवन के निर्माण को अभियान पूर्वक तोड़ा गया। संबंधित निर्माणकर्ता को नोटिस जारी करने के उपरांत स्वत: बिना अनुमति किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

देवउठनी एकादशी पर आज संपूर्ण रायपुर जिले में स्थानीय अवकाश घोषित

रायपुर। देवउठनी एकादशी पर्व के अवसर पर 20 नवंबर को संपूर्ण रायपुर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय, नवा रायपुर सहित रायपुर शहर स्थित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत रायपुर शहर एवं नवा रायपुर क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्रों के शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में भी स्थानीय अवकाश रहेगा। इस प्रकार संपूर्ण रायपुर जिले में स्थानीय अवकाश प्रभावी होगा। यह अवकाश बैंकों, कोषालयों एवं उप कोषालयों पर लागू नहीं होगा।



इंगांकृवि में दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला 26 एवं 27 को

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 26 एवं 27 नवंबर को स्वामी विवेकानन्द सभागार, कृषि महाविद्यालय, रायपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लगभग 250-300 किसान एवं महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य सहित मध्यप्रदेश के 27, उत्तरप्रदेश के 22 तथा उड़ीसा के 09 किसान भाग लेंगे। इसके अलावा बागवानी, मत्स्य, कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों एवं अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाकर मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से जुड़ी नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा प्रदेश में मखाना क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा प्रक्षेत्र विस्तार, बीज उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, बाजार एवं निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कोहरे के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की विशेष तैयारी

रायपुर। सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण ट्रेन परिचालन में आने वाली चुनौतियों से निपटने तथा यात्रियों की संरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। इसी क्रम में रेलवे द्वारा अपने तीनों रेल मंडलों में लगभग 3657 फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। जीपीएस आधारित यह आधुनिक उपकरण घने कोहरे के दौरान लोको पायलटों को रेल मार्ग में आने वाले सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट, रेलवे स्टेशन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सटीक जानकारी प्रदान करने में सहायक हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रेल नेटवर्क भौगोलिक दृष्टि से विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ घने जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। विशेष रूप से खोंगसरा एवं भनवारटंक के आसपास के रेलखंडों में सर्दियों के दौरान घना कोहरा ट्रेन परिचालन को प्रभावित करता है। ऐसे में ट्रेन परिचालन के दौरान लोको पायलटों को सिग्नल एवं रेल मार्ग को देखने में फॉग सेफ डिवाइस महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभाता है। फॉग सेफ डिवाइस एक जीपीएस आधारित नेविगेशन उपकरण है, जो लोको पायलट को रेल मार्ग की पूर्व निर्धारित जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें एक एंटीना लगा होता है, जो जीपीएस सिग्नल प्राप्त करता है। साथ ही, इसकी मेमोरी में संबंधित रेल मार्ग की जानकारी पहले से फीड रहती है। इसमें मार्ग में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन, सिग्नल, मानवित एवं अमानवित समपार फाटक तथा न्यूट्रल सेक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का विवरण दर्ज होता है।

एम्स रायपुर में स्पीड डेटिंग कार्यक्रम रद्द एनएसयूआई की मांग पर प्रबंधन ने लिया फैसला

रायपुर। एम्स रायपुर में ओरियाना फेस्ट के अंतर्गत प्रस्तावित स्पीड डेटिंग कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। एनएसयूआई की आपत्ति एवं मांग के बाद प्रबंधन ने यह फैसला लिया। एनएसयूआई ने संस्थान पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और डिप्टी



डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई ने ज्ञापन में स्पीड डेटिंग कार्यक्रम में अश्लीलता परोसे जाने की आशंका एवं आयोजन की प्रकृति पर आपत्ति जताई। इस दौरान छात्र नेता पुनेश्वर लहरे ने कहा कि फेस्ट के नाम पर शराब परोसना, अश्लीलता को बढ़ावा देना, मादक पदार्थों का सेवन एवं अश्लील गानों को बढ़ावा देना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और अस्मिता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि हम ओरियाना फेस्ट या विद्यार्थियों के मनोरंजन के विरोधी नहीं हैं। हमारा विरोध केवल उन गतिविधियों से है, जो शैक्षणिक संस्थान की गरिमा, सामाजिक-सांस्कृतिक मर्यादा एवं छत्तीसगढ़ की परंपरा और अस्मिता के विपरीत हों।

विद्यालयों का निजीकरण नहीं, भवन और भूमि का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा

रायपुर। सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं विकासखंड मुख्यालयों में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। इनमें 103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। प्रस्ताव के अनुसार इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। इसके तहत चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्था के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि वृद्धि का प्रावधान रहेगा। विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा।

पारिवारिक विवाद में सिलबट्टे से वार कर गला घोंटकर की थी हत्या

मां की हत्या को सामान्य मृत्यु बताकर छिपाने वाला पुत्र गिरफ्तार

रायपुर। पारिवारिक विवाद में अपनी मां की हत्या कर उसे सामान्य मृत्यु दर्शाने और साक्ष्य छिपाने वाले पुत्र को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मर्ग जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं परिजनों व गवाहों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सामने आई। थाना खमतराई पुलिस एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। इसी क्रम में थाना खमतराई के मर्ग क्रमांक 72/2023 की जांच के दौरान मृतिका श्यामा गोस्वामी के सिर में चोट एवं गले में रस्सी के निशान पाए जाने के संबंध में प्राप्त तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन, परिजनों एवं गवाहों से पूछताछ तथा घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की।



जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मृतिका की मृत्यु के पीछे हत्या की आशंका पर विशेष रूप से जांच की गई। जांच में पता चला कि मृतिका का अपने पुत्र संजू उर्फ संदीप गिरि गोस्वामी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था। आरोपी अपनी पत्नी एवं बच्चों को घर लाना चाहता था, जिस बात को लेकर दिनांक 05.07.2023 को उसका अपनी मां से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी मां को दीवार में धक्का दे दिया, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। इसके बाद मृतिका के दर्द से कराहने पर आरोपी ने गुस्से में आकर पास में रखे सिलबट्टे के लोहे से उनके सिर के पीछे वार कर दिया। इससे मृतिका के सिर से खून बहने लगा। इसके बाद आरोपी ने पलंग में लगी मच्छरदानी की रस्सी से उनका गला घोंट दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने घटना को छिपाने के उद्देश्य से मृतिका के सिर में गमछा बांध दिया तथा माथे एवं सिर में गुलाल लगा दिया। आरोपी ने अपनी मां की हत्या की जानकारी अपनी बहनों एवं पुलिस को नहीं दी तथा आसपास के लोगों को मृत्यु का सामान्य कारण बताकर हत्या की घटना को छिपाने का प्रयास किया। प्रकरण में मृतिका की पुत्री संगीता गोस्वामी द्वारा अपनी मां की मृत्यु को लेकर संदेह व्यक्त किए जाने पर पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायत एवं पूर्व में की गई मर्ग जांच से संबंधित तथ्यों का पुन: सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के कथन एवं परिजनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी संजू उर्फ संदीप गिरि गोस्वामी की संलिप्तता सामने आई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना खमतराई पुलिस एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई।

बैंकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस का विशेष अभियान

रायपुर। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा को लेकर नॉर्थ जोन पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। नॉर्थ जोन के पांचों थाना क्षेत्रों में विशेष टीम गठित कर बैंकों, एटीएम एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन बाइक पेट्रोलिंग की गई। बैंक परिसरों एवं आसपास संदिग्ध व्यक्तियों तथा गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में आने-जाने वाले नागरिकों की सुरक्षा तथा बैंक परिसरों के आसपास होने वाली आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) दीपमाला कश्यप द्वारा नॉर्थ जोन के समस्त थाना प्रभारियों को विशेष बैंक सुरक्षा अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में अतिरिक्त



पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन आदित्य पाण्डेय के पर्यवेक्षण में नॉर्थ जोन के पांचों थाना क्षेत्रों में अलग-अलग विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गठित टीमों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थित विभिन्न बैंकों, एटीएम एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में विशेष बैंक बाइक पेट्रोलिंग की। इस दौरान बैंक परिसरों एवं आसपास आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों तथा उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी गई।

साथ ही बैंक प्रबंधन एवं वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से चर्चा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने बैंक में नगदी जमा एवं आहरण करने आने वाले नागरिकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की समझाइश दी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.